सुविचार

"असीमित उत्साहवान व्यक्ति लगभग प्रत्येक कार्य में सफल होता है।" - चार्ल्स श्वॉब

दैनिक

इंटीग्रेटेड ट्रेड

डेवलपमेंट सेंटर न्यूज

आरएनआई नं.
MPHIN/2018/77221
डाक पंजीयन नं.
MP/BHOPAL/4-504/2020-22

आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस | 2018 में स्थापित | ITDCNEWS.COM

वर्ष-5 अंक-183, भोपाल, बुधवार 18 मई 2022, पृष्ठ-8, मूल्य-2 रुपए

मप्र निकाय-पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई पूरी

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, अभी करना होगा इंतजार

भोपाल। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय ‍काय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी ‍बर है। आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में प्रदेश ‍ शिवराज सरकार द्वारा लगाई गई याचिका पर ‍सला नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ‍रक्षित रख लिया है, ऐसे में एमपी में निकाय और ‍चायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे या ‍हीं, इसके लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा।

दरअसल, बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत ‍ौर नगरीय निकाय 2022 में ओबीसी आरक्षण पर ‍ड़ा फैसला सुनाते हुए कहा था कि बिना ओबीसी आरक्षण के प्रदेश में चुनाव करवाएं जाएं और मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिए थे कि 15 दिन के अंदर पंचायत चुनाव एवं नगर पालिका चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वकीलों की टीम से मुलाकात की और देर शाम संशोधन याचिका पेश की है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की । मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में कोर्ट ने सारे तथ्यों को सुनने के राज्य सरकार से कुछ और जानकारी मांगी है। एक बार फिर से कल या परसों मामले पर सुनवाई होगी। कोर्ट से मांगी गई जानकारी को सरकार कराएगी मुहैया। सुत्रों की मानें तो सरकार के आवेदन पर यदि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती है तो राज्य निर्वाचन आयोग इसी सप्ताह चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां कर ली हैं। इसके लिए शिवराज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की वार्डवार रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और पुनर्विचार आवेदन में 2022 के परिसीमन से चुनाव कराने की अनुमति मांगी है।

कांग्रेस नेता का ट्वीट

इधर, कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने ट्वीट कर कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग अगर अपने दायित्वों को समय रहते हुए पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उसके दुष्परिणाम मध्य प्रदेश की जनता नहीं भोगेगी। ओबीसी वर्ग को भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वह अधिकार प्रदेश सरकार और निर्वाचन आयोग को देना होगा।भारतीय संविधान का उल्लंघन करने का अधिकार ना प्रदेश सरकार को है ना निर्वाचन आयोग याचिकाकर्ता सैयद जाफर और जया ठाकुर की तरफ से एडवोकेट वरुण ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दायर आवेदन के दौरान यह बात कही।

फ्रांस पहुंचे अनुराग ठाकुर, भारतीय राजदूत जावेद अशरफ ने किया स्वागत

पेरिस, एजेंसी। केंद्रीय ‍ूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ‍कुर मंगलवार को फ्रांस पहुंचे। ‍हां उनका स्वागत फ्रांस में ‍ारतीय राजदूत जावेद अशरफ ने ‍किया। केंद्रीय मंत्री फ्रांस में ‍तिष्ठित कान फिल्म महोत्सव में ‍ामिल होंगे। 75वें कान फिल्म ‍होत्सव के रेड कार्पेट कार्यक्रम ‍ भारतीय प्रतिनिधिमंडल में ‍ूचना और प्रसारण मंत्री के साथ ‍ंगीतकार ए आर रहमान और ‍वाजुद्दीन सिद्दीकी भी शामिल हो ‍रहे हैं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री ‍होत्सव में शामिल होने के लिए ‍ोमवार रात फ्रांस के लिए रवाना ‍ गए थे। 'मार्चे डू फिल्म्स' या ‍कान फिल्म मार्केट में भारत को ‍आधिकारिक 'कंट्री आफ आनर% ‍ोषित किया गया है। अनुराग ‍कुर मंगलवार शाम को 'रेड कार्पेट' पर चलेंगे और बुधवार को मैजेस्टिक बीच पर मार्चे डू फिल्म के 'ओपनिंग नाइट' समारोह में भी शामिल होंगे। अनुराग ठाकुर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में ए आर रहमान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नयनतारा पूजा हेगड़े, प्रसून जोशी, आर माधवन, रिकी केज, शेखर कपूर, तमन्ना भाटिया, वाणी त्रिपाठी और लोक गायक मामे खान सहित मनोरंजन जगत की शीर्ष हस्तियां शामिल होंगी। तेलुगू एवं तमिल फिल्मों की अभिनेत्री तमन्ना ने ट्वीट किया, कान फिल्मोत्सव के मार्चे डू फिल्म में भारत का प्रतिनिधित्व करना गौरव की बात है। अभिनेता अक्षय कुमार भी आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण वह इसमें शामिल नहीं हो पाए।

चिदंबरम के बेटे के 10 ठिकानों पर सीबीआई रेड

263 चीनी नागरिकों को वीजा के लिए 50 लाख रिश्वत लेने का आरोप, पांच पर केस

नई दिल्ली, एजेंसी। सीबीआई ने मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के 10 ठिकानों पर छापा मारा है। इस दौरान सीबीआई ने कार्ति के खिलाफ नया मामला दर्ज किया गया है। उन पर 263 चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए कथित तौर पर 50 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप है।

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई को आईएनएक्स मीडिया मामले में लेन-देन की जांच के दौरान इसकी जानकारी मिली। बता दें कि वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कथित तौर पर नियमों की अनदेखी कर चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने में मदद की। पंजाब में स्थित तलवंडी साबो पावर लिमिटेड प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसके लिए चीनी मजदूरों को वीजा दिलाया गया था।

क्या है मामला

एक प्राईवेट कंपनी पंजाब के मनसा में 1980 मेगावॉट का थर्मल पावर प्लांट लगा रही थी। इसका जिम्मा चीन की एक कंपनी को दिया गया था। आरोप है कि यह प्रोजेक्ट लेट हो रहा था। आरोप है कि काम को तेजी से कराने के लिए चीनी प्रोफेशनल्स को मनसा लाया गया। इनके लिए वीजा का इंतजाम चेन्नई के एक शख्स ने अपने कुछ साथियों की मदद से किया। इसमें नियमों की अनदेखी हुई।

कुल 263 प्रोजेक्ट वीजा जारी किए गए। इतना ही नहीं होम मिनिस्ट्री को इस प्राईवेट कंपनी ने एक लेटर लिखा और इन तमाम वीजा होल्डर्स को फिर से वीजा जारी करने की गुजारिश की। इसकी मंजूरी भी एक महीने में मिल गई। आरोप है कि चेन्नई के एक व्यक्ति ने अपने सहयोगियों की मदद से 50 लाख रुपए रिश्वत मांगी।

पांच आरोपियों पर केस दर्ज

सीबीआई ने मामले में 5 आरोपियों पर केस दर्ज किया है। इनमें पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम, चेन्नई स्थित करीबी सहयोगी एस. भास्कररमन?, पंजाब की निजी कंपनी के विकास मखरिया, मैसर्स तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, मानसा (पंजाब), मेसर्स बेल टूल्स लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) शामिल हैं। इसके अलावा एक सरकारी अधिकारी और एक निजी कर्मचारी भी शामिल हैं। जांच एजेंसी ने इनके नाम नहीं बताए है।

कार्ति बोले- यह कितनी बार हुआ, मैं भूल गया हूं

कार्रवाई के दौरान कार्ति चिदंबरम ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि यह (सीबीआई की कार्रवाई) कितनी बार हुआ है, मैं गिनती भी भूल गया हूं। इसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। बता दें कि सीबीआई ने 2010-2014 के बीच के इस मामले में नया केस दर्ज किया है। उसी मामले में आज की कार्रवाई की गई है।

गेट फांद कर घर के अंदर घुसे सीबीआई अफसर

सीबीआई तमिलनाडु में तीन, मुंबई में तीन, पंजाब में एक, कर्नाटक में एक और ओडिशा में एक सहित नौ स्थानों पर तलाशी ले रही है। इसमें ऑफिस और घर शामिल हैं। दिल्ली में पी चिदंबरम के घर का गेट बंद होने के कारण सीबीआई के अधिकारी गेट फांद कर अंदर घुसे। सूत्रों के मुताबिक, कार्ति चिदंबरम के खिलाफ कथित विदेशी निवेश को लेकर सीबीआई ने यह कार्रवाई की है। छापेमारी सुबह आठ बजे शुरू हुई। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये मामला साल 2007 का है और आईएनएक्स मीडिया कंपनी से जुड़ा है। इसकी डायरेक्टर शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी थे। इस मामले में ये दोनों भी आरोपी हैं।

मनी लांड्रिंग मामला

बनर्जी दंपती से कोलकाता में ईडी की पूछताछ

नई दिल्ली। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ करने वाला है। इसे लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है। कोर्ट ने कहा कि कि में किसी तरह का दखल सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाला को लेकर मनी लांड्रिंग केस में दिल्ली के बजाय कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से पूछताछ करेगी।

बता दें कि इस मामले में ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को पहले ही समन जारी कर दिया है। ईडी ने पहले की एक घटना का जिक्र किया और बताया कि किस प्रकार सीबीआइ अधिकारियों का कोलकाता में घेराव किया गया था। ईडी ने अभिषेक बनर्जी को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति बताया। इससे पहले जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने बंगाल में कथित कोयला तस्करी मामले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में उन्हें जारी किए गए समन को रद करने के अनुरोध वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वे मामले में जांच को नहीं रोक रहे हैं और ईडी कोलकाता आकर मामले में जांच कर सकती है।

3 पुलिसकर्मियों के हत्याकांड के मामले में डॉ. नरोत्तम मिश्रा का बयान

इस केस में ऐसी कार्रवाई करेंगे जो इतिहास में नजीर बन जाएगी

गुना। 3 पुलिसकर्मियों के हत्याकांड के ‍मामले में फरार चल रहे एक और आरोपी छोटू ‍पठान का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। ‍मध्य प्रदेश के गुना के आरोन में पुलिस को देर ‍रात आरोपी की रुठियाई इलाके में लोकेशन ‍मिली थी, तभी से पुलिस उसका पीछा कर रही ‍थी। मंगलवार सुबह धरनावदा थाना इलाके के ‍अंतर्गत हरिपुर के जंगल में भदोली रोड़ पर ‍आरोपी छोटू पठान को पुलिस ने ढेर कर दिया। ‍इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट ‍करते हुए कहा है कि फरारी नहीं, अपराधियों को ‍तत्काल सरेंडर करना चाहिए। गुना जिले के ‍धर्मावदा भदोली मार्ग पर तड़के छोटू उर्फ जहिर ‍के होने की सूचना मिली, सूचना पर पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई। छोटू ने सरेंडर करने के स्थान पर पुलिस पर फायरिंग की जिसमें एक पुलिस आरक्षक को गोली लगी है और गाड़ी पर भी गोलियां लगी है, जवाबी कार्यवाही में अपराधी छोटू मारा गया। अभी दो और लोग फरार है।

'नजीर' पेश कर रही है एमपी सरकार

इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि फरार चल रहे दो और आरोपियों को फिर चेतावनी दे रहा हूं कि वे सरेंडर करें। मेरा लगातार कहना है कि इस केस में ऐसी कार्रवाई करेंगे जो इतिहास में नजीर बन जाएगी।

एक और आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर

गुना जिले में शिकारियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ के बाद तीन पुलिसकर्मियों के शहीद होने के मामले में आज तड़के एक और आरोपी छोटू पठान पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया, इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। बता दें, देर रात पुलिस को रुठियाई इलाके में आरोपी की लोकेशन मिली थी, तभी से पुलिस पार्टी उसका पीछा कर रही थी। मिली जानकारी के मुताबिक गुना से आरोपी छोटू पठान राजस्थान की ओर भागने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिलते ही एक टीम तत्काल उस स्थान की ओर पहुंची। दोनों पक्षों में आमने-सामने की मुठभेड़ में छोटू पठान मारा गया।

केंद्र ने गेहूं निर्यात प्रतिबंध के आदेश में दी ढील, कस्टम विभाग के पास पहले से रजिस्टर्ड खेप को अनुमति

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध के आदेश में कुछ ढील देने का मन बनाया है। सरकार के ओर से यह घोषणा की गई है कि 13 मई से पहले जो भी गेहूं की खेप कस्टम विभाग को सौंप दी गई थी। या फिर उसका विवरण उनके सिस्टम में दर्ज कर लिया गया है। ऐसी गेहूं की खेपों को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी।

गेहूं निर्यात के प्रतिबंध में ढील देते हुए सरकार ने मिस्र को दी जाने वाली गेहूं शिपमेंट को भी अनुमति दे दी है। गेहूं की यह खेप कांडला पोर्ट पर लोड हो रही थी, जिसे प्रतिबंध के बाद रोक दिया गया था। मिस्र सरकार की सरकार ने भी भारतीय सरकार से कांडला पोर्ट पर लोड हो रही गेंहू की खेप को अनुमति देने का आग्रह किया था।

खाद्य सुरक्षा को लेकर लिया फैसला

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने देश में खाद्य सुरक्षा स्थिति का प्रबंधन करने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही सरकार ने वैश्विक बाजार में अचानक बदलाव से प्रतिकूल रूप से प्रभावित और पर्याप्त गेहूं की आपूर्ति तक पहुंचने में असमर्थ पड़ोसी देशों की जरूरतों का समर्थन करने के लिए यह फैसला लिया था।

पूर्व में की गई प्रतिबद्धताओं को मंजूरी

सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक यह प्रतिबंध उन मामलों में भी लागू नहीं होगा जहां निजी व्यापार द्वारा क्रेडिट पत्र के जरिए पूर्व में प्रतिबद्धताएं की गई हैं। साथ ही ऐसी स्थिति जहां सरकार ने स्वंय अन्य देशों की सरकारों के अनुरोध पर उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने की अनुमति दी है ।

दिवंगत पायलट के घर पहुंचे मुख्यमंत्री, दी श्रद्धांजलि

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश ‍बघेल ने मंगलवार को दिवंगत ‍कैप्टन गोपाल कृष्ण पंडा के रायपुर ‍शैलश्री विहार स्थित आवास पर ‍पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ‍उन्होंने कैप्टन पंडा के चित्र पर ‍पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। ‍इस दौरान उन्होंने कैप्टन पंडा के ‍परिजनों से मिल कर अपनी शोक ‍संवेदनाएं व्यक्त की और उन्हें ‍ढांढस बंधाया। राज्य सरकार के ‍विमानन विभाग के सीनियर पायलट कैप्टन गोपाल कृष्ण पंडा लंबे समय से मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर पायलट थे। 12 मई की रात रात्रिकालीन उड़ान की प्रशिक्षण शार्टी के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। आनन-फानन में उसमें सवार कैप्टन पंडा और नागरिक विमानन महानिदेशालय के प्रशिक्षक कैप्टन ए.पी. श्रीवास्तव को अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना के समय मुख्यमंत्री दिल्ली से उदयपुर की यात्रा पर थे। वे वहां 13 से 15 मई तक आयोजित कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर में शामिल होने पहुंचे थे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश निर्मित दो युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को किया लान्च

मुंबई, एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को स्वदेश निर्मित दो युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को मुंबई के मझगांव डाक्स में लान्च किया। कार्यक्रम के शुभारंभ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कोविड और यूक्रेन में चल रहे उथल पुथल के बीच इन विध्वंसकों का निर्माण व शुभारंभ हमारी समुद्री क्षमता और आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है।

मझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) ने कहा कि यह पहली बार है कि स्वदेशी रूप से निर्मित दो युद्धपोतों को एक साथ लान्च किया गया है। एमडीएल एक प्रमुख जहाज और पनडुब्बी निर्माण रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। सूरत प्रोजेक्ट 15बी डिस्ट्रायर्स का चौथा जहाज है, जो पी15ए (कोलकाता क्लास) डिस्ट्रायर्स के एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत करता है, और इसका नाम गुजरात की वाणिज्यिक राजधानी और मुंबई के बाद पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक केंद्र, नौसेना के नाम पर रखा गया है। कहा।

आंध्र प्रदेश के पर्वत के नाम पर उदयगिरी प्रोजेक्ट

प्रोजेक्ट 15बी श्रेणी के जहाज नौसेना की अगली पीढ़ी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक हैं जिन्हें एमडीएल में बनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया उदयगिरी प्रोजेक्ट 17ए फ्रिगेट्स का तीसरा जहाज है। यह पी17 का अनुसरण है। नौसेना ने कहा कि फ्रिगेट्स (शिवालिक क्लास) में बेहतर स्टील्थ फीचर्स, उन्नत हथियार और सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम हैं। नया युद्धपोत पूर्ववर्ती उदयगिरी, लिएंडर क्लास एएसडब्ल्यू फ्रिगेट का नया अवतार है, जिसने फरवरी 1976 से अगस्त 2007 तक तीन दशकों में फैले देश के लिए अपनी शानदार सेवा में कई चुनौतीपूर्ण आपरेशन देखे।

न्यूज ब्रीफ

भारत माता का नाम विश्व पटल पर रोशन करें खिलाड़ी : मंत्री पटेल

भोपाल। किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने खिलाड़ियों से आहवान किया कि बेहतर खेल से वे भारत माता का नाम विश्व पटल पर रोशन करें। मंत्री श्री पटेल प्रकाश तरण पुष्कर में एक दिवसीय तैराकी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर रहे थे। भोपाल तैराकी समिति अध्यक्ष श्री रामकुमार खिलरानी ने बताया कि प्रतियोगिता में 154 खिलाड़ियों ने 132 इवेन्ट में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला क्रीड़ा अधिकारी जोस चाको ने की। भोपाल तैराकी संघ के अध्यक्ष श्री अनिल अग्रवाल भी मौजूद थे।

सप्ताह में एक दिन भोपाल से होकर चलेगी मुंबई से गोरखपुर के बीच स्पेशल ट्रेन

भोपाल। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। मुंबई से लेकर गोरखपुर के बीच एक विशेष ट्रेन शुरू हो रही है। यह भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से होकर चलेगी। लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस के मध्य तीन-तीन ट्रिप स्पेशल ट्रेन इटारसी स्टेशन पर भी रुकेगी। कन्फर्म टिकट वाले यात्री ही इस ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं।

ट्रेन नंबर : 02103

ट्रेन का नाम = लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन
चलेगी = 16 मई से 30 मई तक हर सोमवार
प्रारंभिक स्टेशन = लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन से सुबह 5.15 बजे

ट्रेन नंबर : 02104

ट्रेन का नाम = गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल ट्रेन
चलेगी = 18 मई से 1 जून तक हर बुधवार
प्रारंभिक स्टेशन = गोरखपुर स्टेशन से सुबह 3 बजे
हॉल्ट = कल्याण, इगतपुरी, नासिक रोड, भुसावल, खण्डवा, इटारसी, रानी कमलापति, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई, उरई, कानपुर सेंट्रल, फतेहपुर, प्रयागराज जंक्शन, ज्ञानपुर रोड, बनारस, वाराणसी जंक्शन, औनिहार, मऊ, बेल्थरा रोड, भटनी एवं देवरिया सदर स्टेशनों पर रुकेगी।

कोलार 6 लेन प्रोजेक्ट : अतिक्रमण टूटेंगे

11 किमी रोड के लिए 26 मई को खुलेंगे टेंडर, 233 करोड़ रु. से बनेगी

भोपाल

राजधानी भोपाल के कोलार रोड को कोलार तिराहे से गोल जोड़ तक (करीब 11 किमी) सड़क सिक्स लेन में बदला जाएगा। इसके लिए अप्रैल में टेंडर लग चुके हैं, जो 26 मई को खुलेंगे। इसमें कुल 233 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पीडब्ल्यूडी अतिक्रमण चिंह्वित कर रहा है। ताकि, टेंडर प्रोसेस के तुरंत बाद काम शुरू किया जा सके। कोलार में करीब 4 लाख आबादी रहती है, जिसे सिक्स-लेन का फायदा मिलेगा। बार-बार लगने वाले जाम से भी राहत होगी। पहले यह सड़क फोरलेन होनी थी, लेकिन बाद में प्रोजेक्ट में बदलाव किए गए। अब यह सिक्स लेन बनेगी। इसलिए लागत भी बढ़ गई है। डिवाइडर, लाइटिंग, फुटपॉथ भी बनाए जाएंगे। टेंडर होने के बाद अक्टूबर 2024 तक काम पूरा होने की बात कही जा रही है।

100 से ज्यादा कॉलोनियां:- कोलार रोड के गोल जोड़ से बैरागढ़ चिचली के बीच की लंबाई 11 चद्व है। इस बीच सर्व-धर्म, मंदाकिनी, बीमाकुंज, कान्हाकुंज, सीआई, चूना भट्?टी एरिया, नयापुरा, ललितानगर, गेहूंखेड़ा, पुलिस हाउसिंग सोसायटी, नहर की पुलिया समेत कई बड़े इलाके आते हैं। इस रोड से 100 से अधिक कॉलोनी के लोगों का आना-जाना होता है।

पिक अवर्स में ट्रैफिक का खासा दवाब:- वर्तमान में रोड पर ट्रैफिक का खासा दवाब रहता है। खासकर सुबह 10 से 12 बजे और शाम 5 से 8 बजे के बीच। इस कारण जाम के हालात भी बनते हैं। इसलिए पीडब्ल्यूडी ने रोड को सिक्स लेन में बदलने का प्रोजेक्ट तैयार किया है। हालांकि, कलियासोत नदी पर ब्रिज बनने के बाद थोड़ा ट्रैफिक शाहपुरा होते हुए दानिशकुंज, मंदाकिनी की ओर चला जाता है। बावजूद हर रोज जाम के हालात बनते हैं। हालांकि, सिक्स लेन के निर्माण के दौरान लोग दूसरे रास्तों से आ-जा सकेंगे। उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी।

सर्व-धर्म ब्रिज के पास एक और ब्रिज बनेगा:- मौजूदा सर्व-धर्म ब्रिज के पास 10 मीटर चौड़ा एक और ब्रिज बनेगा। इससे ट्रैफिक आसानी से गुजर सकेगा। पीडब्ल्यूडी की ब्रिज शाखा इस पर काम कर रही है। वर्तमान ब्रिज काफी संकरा है। यहां अक्सर जाम लगता है।

सिक्स लेन में यह

- 10.5 मीटर-10.5 मीटर चौड़ा रोड बनेगा।
- दोनों ओर 3-3 मीटर चौड़े फुटपाथ बनेंगे।
- फुटपाथ पर पेविंग ब्लॉक लगेंगे।
- फुटपाथ के बाद डेढ़ मीटर का एरिया पोल के लिए।
- सेंटर लाइटिंग होगी। इससे अंधेरे की समस्या दूर हो जाएगी।
- बीचोंबीच डिवाइडर भी बनाए जाएंगे।

अतिक्रमण हटाएंगे:- पीडब्ल्यूडी अफसरों का कहना है कि सिक्स लेन निर्माण के दौरान कुछ अतिक्रमण भी आ रहा है। इसलिए इसे हटाया जाएगा। कोलार गेस्ट हाउस के पास, सर्व-धर्म एरिया में अतिक्रमण है।

इसी महीने खुलेंगे टेंडर:- कोलार रोड सिक्स लेन प्रोजेक्ट के टेंडर इसी महीने खुलेंगे। इसके बाद काम की शुरुआत करेंगे।

संजय मस्के,
चीफ इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी

निटर, भोपाल के पूर्व छात्र श्री हसन शेख मेहमूद दूसरी बार बने सोमालिया राष्ट्रपति

निटर, भोपाल में मास्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पाठ्यक्रम के 1986-88 सत्र में अध्यनरत् श्री हसन शेख मेहमूद सोमालिया के दूसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए है। निटर, भोपाल के निदेशक श्री सी.सी. त्रिपाठी ने श्री शेख को बधाई देते हुए कहा कि निटर, भोपाल के लिये यह बड़े गौरव की बात है कि श्री हसन शेख मेहमूद ने अपने छात्र जीवन का महत्वूर्ण समय निटर, भोपाल में बिताया है। निटर, भोपाल परिवार अपने इस पूर्व प्रिय विद्यार्थी की उपलब्धि पर गौरवान्वित है।

निटर, भोपाल के जनसंपर्क अधिकारी प्रो. पी.के. पुरोहित ने बताया कि महामहिम श्री हसन शेख मेहमूद सोमालिया के राष्ट्रपति के प्रथम कार्यकाल में दिनांक 31 अक्टूबर 2015 को एक विशेष दीक्षांत समारोह में भाग लेने भोपाल आये थे। निटर, भोपाल परिवार ने गरिमामय समारोह में उनका भव्य स्वागत किया था।

निटर, भोपाल में श्री हसन शेख ने उनके छात्र जीवन में बनी फिल्म का अवलोकन किया था। जिसे संस्थान द्वारा सहेज कर रखा गया था। श्री हसन शेख मेहमूद ने अपने उद्बोधन में अपने पुराने दिनों के साथियों एवं शिक्षकों को याद करते हुए सभी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर शुभकामनाएं ली थी। श्री शेख ने अपने उदबोधन में कहा था कि उनके द्वारा भोपाल से प्राप्त की गई शिक्षा अफ्रीकी देशों की प्रगति में उनके योगदान के लिये बहुत सहायक रही है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर का पुष्प-गुच्छ और चंदेरी का प्रसिद्ध अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया।

सट्टा किंग के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर

मुक्त कराई 4.20 करोड़ रूपये की 6 हजार वर्ग फुट शासकीय भूमि

भोपाल

जबलपुर जिला प्रशासन, पुलिस एवं नगर निगम की सयुंक्त कार्यवाही में सोमवार को गोरखपुर तहसील के आदर्श नगर रामपुर में कुख्यात अपराधी सट्टा किंग सतीश सनपाल के अवैध निर्माणों को जेसीबी मशीनों से ध्वस्त करने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही में करीब 4 करोड़ 20 लाख रूपये की शासकीय भूमि मुक्त कराई गई और लगभग 80 लाख रूपये के निर्माण को ध्वस्त किया गया। सतीश सनपाल द्वारा अपने आलीशान बंगले से लगी नाले एवं उसके आसपास की लगभग 6 हजार वर्गफुट बेशकीमती शासकीय भूमि पर कब्जा कर बाउंड्रीवाल और लॉन का निर्माण किया गया था, जिसे आज अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

भोपाल के हर वार्ड में खुलेगा एक अस्पताल : 37 सीएम संजीवनी क्लीनिक और 30 पॉली क्लीनिक होंगे शुरू

भोपाल

राजधानी के लिए अच्छी खबर है। भोपाल के शहरी इलाकों में 56 और बैरसिया के बसई में एक नया अस्पताल खोला जाएगा। केन्द्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के फंड में शहर में 57 शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं की मंजूरी दी है। इनमें 30 पॉली क्लीनिक और 37 मुख्यमंत्री संजीवनी शुरू किए जाएंगे। इन अस्पतालों के लिए स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन के अफसरों ने जगह की तलाश शुरू कर दी है। अधिकांश क्लीनिक के लिए स्थान तय हो चुका है। कुछ जगहों पर पुराने भवनों को रेनोवेट कर

अत्याधुनिक क्लीनिक बनाया जाएगा। एक क्लीनिक के लिए अनुमानित 25 लाख रूपए तय किए गए हैं।

इन 14 संस्थाओं को पॉली क्लीनिक में किया जाएगा अपग्रेड:- अभी राजधानी के शहरी क्षेत्र में सीएचसी, यूपीएचसी, सिविल डिस्पेंसरी और संजीवनी क्लीनिक को मिलाकर कुल 50 शहरी स्वास्थ्य संस्थाएं संचालित हैं। इनमें से आठ सिविल डिस्पेंसरी और छह संजीवनी क्लीनिक को पॉली क्लीनिक में अपग्रेड किया जाएगा।

सिविल डिस्पेंसरी 8: अहमदाबाद, प्रोफेसर कॉलोनी, सेवनियां गौंड(सूरज नगर), कमला नगर, 1100 क्वार्टर, बाग सेवनियां, आनंद नगर,

संजीवनी क्लीनिक 6: नारियल खेड़ा, पटेल नगर(भारत टाकीज के पास), लक्ष्मण नगर, अमरावद खुर्द, बैरागढ़ चीचली, विश्वकर्मा नगर

पॉली क्लीनिक में मिलेंगे तीन एक्सपर्ट

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पॉली क्लीनिक में एक मेडिकल ऑफीसर के अलावा तीन विशेषज्ञ डॉक्टर भी उपलब्ध रहेंगे। स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ और एमडी मेडिसिन यहां मरीजों का उपचार करेंगे। फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफीसर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, काउंसलर, ड्रेसर, सिक्योरिटी गार्ड के अलावा एक सपोर्ट स्टाफ भी तैनात किया जाएगा। इन क्लीनिक्स में 45 प्रकार की जांचें और 121 प्रकार की दवाएं फ्री मिलेंगी।

डेंगू रोकने जन-जागरुकता बढ़ाएँ : स्वास्थ्य मंत्री

भोपाल

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि डेंगू की रोक थाम के लिए जन-जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने यह बात डेंगू दिवस के अवसर पर कही। उन्होंने जयप्रकाश जिला चिकित्सालय से डेंगू बुखार के मच्छरों से बचाव का संदेश देने जन-जागरूकता साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि प्रति वर्ष 16 मई को डेंगू दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि डेंगू एक प्रकार का डेन वायरस से होने वाली बुखार बीमारी है। इस पर नियंत्रण रखने के लिए

तुरंत जाँच आवश्यक है। डेंगू की जाँच की सुविधा प्रदेश के सभी जिलों में निःशुल्क उपलब्ध है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि डेंगू से बचाव बहुत जरूरी है। इसके लिए घर-घर संदेश देना होगा कि साफ पानी को ज्यादा समय जमा नहीं रखें। घर में रखे गमले, कूलर पुराने टायर आदि में पानी जमा नहीं होने दें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है और दिन में काटता है। उन्होंने कहा कि हमें लोगों को जागरूक करना होगा। संचालक आईईसी श्री बसंत कुर्रे और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

दैनिक
इंटीग्रेटेड ट्रेड
डेवलपमेंट सेंटर न्यूज
मध्य भारत का एक विश्वसनीय दैनिक
98 26 22 00 22

अर्थव्यवस्था, शिक्षा, नियोजन, उद्भव, पर्यावरण, मनोरंजन.

आपकी बात
आपके साथ

छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि और आजीविका मॉडल को मिली सराहना

श्रीनगर में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में कृषि उत्पादन आयुक्त ने दिया प्रस्तुतीकरण

रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में कृषि को समृद्ध और किसानों को खुशहाल बनाने तथा कृषि आधारित गतिविधियों के माध्यम से गांवों में रोजगार और लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों को देश के अन्य राज्यों ने जाना, समझा और सराहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि और आजीविका मॉडल को जानने और समझने के लिए ''प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से नागरिकों और सरकार को करीब लाने'' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में छत्तीसगढ़ को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है । श्रीनगर में आयोजित इस राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ कमलप्रीत सिंह ने छत्तीसगढ़ में सतत कृषि और आजीविका विकास के मॉडल के बारे में विस्तार से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुति दी।

यहां यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य बीते साढ़े 3 सालों में कृषि के क्षेत्र में मॉडल राज्य के रूप में उभरा है। छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों और कार्यक्रमों के चलते राज्य में कृषि उत्पादन, उत्पादकता एवं किसानों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

राज्य में कृषि उत्पादन, उत्पादकता और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए संचालित राजीव गांधी किसान योजना से कृषि को प्रोत्साहन मिला है। सुराजी गांव योजना के नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी कार्यक्रम और गोधन न्याय योजना से गांवों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। गौठान और गोधन न्याय योजना से राज्य में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा मिला है। ग्रामीण पशुपालक किसानों को पशुधन के देखरेख, उनके चारे- पानी के प्रबंध की चिंता दूर हो गई है।

गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपए किलो में क्रय किए जा रहे गोबर से पशुपालक किसानों को अतिरिक्त लाभ होने लगा है। पशुपालन राज्य में अब आय का जरिया बन गया है। राज्य के 8397 गांव में निर्मित एवं संचालित गौठानों में अब तक 69.28 लाख क्विंटल गोबर का क्रय किया गया है, जिसके एवज में गोबर विक्रेता पशुपालकों और ग्रामीणों को 138 करोड़ 56 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। क्रय गोबर से 19 लाख क्विंटल से अधिक कंपोस्ट खाद का निर्माण कर महिला समूह ने 33 करोड़ 40 लाख की आय अर्जित की है। कंपोस्ट खाद का खेती में उपयोग होने से खाद्यान्न की गुणवत्ता और उत्पादकता बेहतर हुई है। कृषि की लागत में कमी आई है। छत्तीसगढ़ में पशुओं की खुली चढ़ाई प्रथा पर रोक लगी है। इससे पशुओं से फसल हानि रुकी है। कृषि उत्पादकता और दोहरी फसल का रकबा बढ़ा है। गौठान में पशुधन के चारे के प्रबंध के लिए राज्य में पैरादान अभियान से खेतों में पराली जलाने की समस्या से छुटकारा मिला है, जिसके चलते पर्यावरण को होने वाले नुकसान और कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। राज्य के किसानों ने गौठानों को 20 लाख क्विंटल पैरा दान किया है, जिसका मूल्य लगभग 40 करोड़ रुपए है।

राज्य के गांवों में स्थापित गौठानों से 12,013 महिला स्व- सहायता समूह जुड़े हैं, जिनकी सदस्य संख्या 82725 है। महिला समूह गौठनों में स्थापित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट प्लस के उत्पादन के साथ ही कई तरह के अन्य उत्पाद तैयार कर रही हैं।

विभिन्न आय मूलक गतिविधियां जिसमें सब्जी उत्पादन, मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, बटेर पालन, मशरूम उत्पादन, शहद उत्पादन, मसाला निर्माण, साबुन ,डिटर्जेंट, अगरबत्ती का निर्माण चौन फेंसिंग तार, फेंसिंग पोल बनाने के साथ ही दाल मिल, तेल मिल, मिनी राइस मिल सहित वनोपज प्रसंस्करण यूनिट आदि का संचालन कर रही हैं। इससे महिला समूह को अब तक 65 करोड़ 45 लाख रुपए की आय हुई है। गौठानों में गोबर से विद्युत उत्पादन की शुरुआत हो चुकी है। गोबर से नेचुरल पेंट बनाने के लिए प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, इससे गावों में रोजगार और ग्रामीणों के आय में वृद्धि होगी।

भद्राक्ष को खड़े होने में भी थी दिक्कत, गंभीर कुपोषण से आये बाहर

पोषण पुनर्वास केंद्रों में पौष्टिक आहार से रेयांश एवं भद्राक्ष की लौटी मुस्कान'

कोरिया। जिले में कुपोषण मुक्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों में पोषण पुनर्वास केंद्र नौनिहालों के लिए वरदान साबित हुए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर में स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र में उचित देखभाल से मात्र 6 दिन में ही विकासखण्ड भरतपुर के ग्राम जनकपुर के रेयांश का वजन 8.500 किलोग्राम से 8.850 किलोग्राम हो गया। इस माह के शुरुआत में रेयांश को एनआरसी में भर्ती किया गया था और 01 सप्ताह के भीतर ही वजन सुधार हुआ। रेयांश की माता श्रीमती जनकलली ने बताया कि पोषण पुनर्वास केंद्र में अच्छी सुविधा, समय पर दवाइयों, पोषण आहार तथा चिकित्सकों के परामर्श से अब रेयांश के स्वास्थ्य में सुधार आया है। उन्होंने बताया कि भोजन में यहां पौष्टिक दलिया, सूजी, पोहा, खिचड़ी, दूध, अंडा, फल दिया जाता है तथा बच्चों के मनोरंजन के लिए खिलौने की भी व्यवस्था है।

एनआरसी में बेहतर देखभाल, चिकित्सकीय परामर्श, दवाइयों तथा पोषण आहार से जिले में कुपोषण दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। जिले में 4 हजार 476 बच्चों ने अब तक कुपोषण के खिलाफ जंग में पोषण पुनर्वास केंद्र के माध्यम से जीत हासिल की है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां के पोषण पुनर्वास केंद्र में ग्राम कटकोना के भद्राक्ष का वजन केंद्र में आने के समय 7.500 किलोग्राम था जो मात्र 10 दिनों में बढ़कर 8.540 किलोग्राम हो गया। भद्राक्ष की माता ने बताया कि 24 अप्रैल को भद्राक्ष को एनआरसी में भर्ती किया गया। यहाँ आने से पहले वह अति गम्भीर कुपोषण की श्रेणी में था, जिसकी वजह से ठीक से खड़े होने में भी समस्या होती थी। लेकिन चिकित्सकों के देखभाल एवं दवाईयों के प्रभाव से उसके खानपान में सुधार आया है। उन्होंने बताया कि केंद्र में चिकित्सकों द्वारा घर पर खान-पान में रखे जाने वाली सावधानियों के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी है।

वर्तमान में जिले में कुल 05 पोषण पुनर्वास केन्द्रों में कुपोषित बच्चों को रखकर कुपोषण मुक्ति हेतु देखभाल किए जा रहे हैं। जिनमें जिला अस्पताल बैकुण्ठपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनेन्द्रगढ़, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जनकपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनहत, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खड़गवां में पोषण पुनर्वास केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों में चिकित्सा विशेषज्ञों, प्रशिक्षित स्टाफ नर्स, फीडिंग डेमोस्ट्रेटर व कुक द्वारा चिकिसकीय सुविधा के साथ-साथ पोषण आहार व बेहतर वातावरण में 15 दिवस तक इलाज किया जाता है साथ ही शिशुओं के लिए 2 हजार 250 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है।

कांग्रेस करती है तुष्टीकरण की राजनीति : प्रबल प्रताप सिंह जूदेव

कोरिया। जेल भरो आन्दोलन मे सहभागिता निभाते भाजपा नेता प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने छत्तीसगढ की कांग्रेस सरकार पर अनेक गंभीर आरोप लगाते हुए हाल ही मे छत्तीसगढ सरकार व्दारा लाए गए कानून को काला कानून कहकर जेल भरो आन्दोलन मे ~~सहभागिता निभाई ज्ञात हो की~~ कोरिया में आयोजित धरना प्रदर्शन में कांग्रेस की भूपेश सरकार पर हमला करते हुवे प्रबल प्रताप सिंह जुदेव हसदेव की सुरक्षा का मुद्दा आंदोलन में उछालते हुए भूपेश सरकार को घेरने का प्रयास किया। प्रबल ने आगे भूपेश सरकार की नाकामी बता वायदाखिलाफ़ी के मुद्दे पर प्रहार किया। प्रबल ने धर्मांतरण व गौरक्षा के मुद्दे पर भी भूपेश सरकार को जमकर घेरा। राज्य में दिनों दिन बढ़ रही बिजली की समस्या, प्रधानमंत्री आवास के मुद्दे, स्व.सहायता समूहों से रेडी टू ईट छिनने के मुद्दे और तुष्टिकरण की घटिया राजनीति पर कांग्रेस को चारों तरफ से घेरने का पूरा प्रयास किया। प्रबल ने भूपेश सरकार पर धर्मांतरण कराने का गंभीर आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ की अस्मिता व संस्कृति पर वार होना बताया है। कांग्रेस की भूपेश सरकार में वनवासियों के जल, जमीन व जंगल का सौदा होने पर गहरा दुःख व्यक्त किया और कहा कि कांग्रेस ने गत तीन साल में राज्य में विकास काड पहिया रोक दिया है जिससे मूलभूत सुविधाएं आमजनों तक नहीं पहुँच पा रही है। इस नाकामी के लिए भूपेश सरकार की तानाशाह रवैया व हीटलरी कार्यप्रणाली को जिम्मेदार ठहराया है।इस अवसर पर भैया लालरजवाड़े, चम्पा देवी पावले,श्याम बिहारी जैसवाल,कृष्ण बिहारी जैसवाल और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

46 डिग्री तापमान के बाद भी आंगनबाड़ी केंद्र बंद नहीं - यादव

मुंगेली। लोरमी - भाजपा महामंत्री सुशील यादव ने कलेक्टर महोदय से मांग करते हुए कहा अप्रैल-मई के महीना में 40 से 46 डिग्री तापमान चल रही है उसके बाद भी आंगनवाड़ी केंद्र को संचालित रखे हुए हैं इसमें सबसे कम उम्र के बच्चे ही पढ़ने आते हैं उसके बाद भी इस विभाग में केंद्र बंद करने का आदेश जारी नहीं किया गया है जबकि शिक्षा विभाग में शाला बंद करने का आदेश जारी हो गया है और शाला बंद है इसमें छोटे-छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गर्मी में आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करने के लिए विभाग से आदेश जारी हो जाना था बच्चों के लिए नाश्ता पैकेट या रेडी टू ईट का वितरण कार्यकर्ताओं के द्वारा होते रहना चाहिए श्री यादव जी ने कलेक्टर महोदय जी से आग्रह करते हुए जिला स्तरीय पर ही निर्णय लेते हुए 15जुलाई तक आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करने का आदेश जारी करने की मांग किए।

हेमकेश्वर गहवई चुने गये गहवई कुर्मी क्षत्रिय समाज युवा संगठन के जिला अध्यक्ष

हरजीत कुमार

मुंगेली। गहवई कुर्मी क्षत्रिय समाज युवा संगठन के बिलासपुर राज से जिला अध्यक्ष के लिए रविवार को ग्राम बावली में चुनाव रखा था इसमे नवयुवक संगठन के लिए जिला अध्यक्ष पद के लिए हेमकेश्वर गहवई ग्राम पीपरलोड़ वाले को जिला अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया । हेमकेश्वर गहवई ने कहा कि समाज में समाजिकता कुप्रथाओ को दूर करते हुए समाज हित में कार्य करते हुए जो छात्र छात्राओं को समाज द्वारा सम्मानित किया जायेगा जिसे समाज में आगे चलकर सहभागिता रहेगा । इसमें महिला संगठन जिला अध्यक्ष के लिए तीजन बाई वर्मा ग्राम पकरिया वाले को महिला जिला अध्यक्ष के लिए निर्विरोध चुनी गई । चुनाव में दुर्ग बेमेतरा राज के लेखराम वर्मा , गोपाल वर्मा , बिलासपुर राज के राज प्रधान राजकुमार वर्मा , उपध्यक्ष कमल वर्मा , सह . सचिव अनिल वर्मा , श्याम जी वर्मा , अशोक कौशिक , युगल वर्मा , सोहन वर्मा , नारायण वर्मा , शिवकुमार गहवई , बलदाऊ वर्मा , नागेश्वर , दुष्यंत कौशिक , राजेन्द्र वर्मा , किशकुमार वर्मा , मांशु वर्मा , रुपेन्द्र कौशिक , इसके अलावा परमेश्वर गहवई , एवं समस्त बिलासपुर राज के नवयुवक सम्मिलित थे

ससुराल गये व्यक्ति की बाइक चोरी

सरायपाली। सरायपाली थाना अंतर्गत ग्राम बिजातीपाली में ससुराल गये व्यक्ति का मोटर सायकल चोरी, जिसपर मामला दर्ज किया गया है. चक्रधर चौहान ने पुलिस को बताया कि कुछ वर्ष पूर्व वह एक सीडी डिलक्स मोसा क्र. सीजी04डीएक्स1934 सेकण्ड हैण्ड मोटर सायकल को चण्डीभौना निवासी धनुर्जय सिदार [illegible] था नाम ट्रांसफर नहीं हुआ था। उक्त मोटर सायकल से वह 14 अप्रैल 2022 की सुबह 09 बजे अपने ससुराल बिजातीपाली गया था। मोटर सायकल को 10 बजे डेड़ साला गंगा प्रसाद के घर के सामने खड़ी कर घर अंदर गया था। कुछ देर बाद बाहर निकलकर देखा तो जहां मोटर सायकल खड़ी किया था वहां पर मोटर सायकल नहीं था आसपास पता तलाश किये पता नहीं चला कोई अज्ञात चोर उसके मोटर सायकल को चोरी कर ले गया है। मामले की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोर के विरूद्ध अपराध धारा 379- आईपीसी अपराध पंजीबद्ध कर [illegible]

बेमेतरा में कृषि मंत्री आज लेंगे समीक्षा बैठक

रायपुर। प्रदेश के कृषि विकास एवं कल्याण, जैवप्रौद्योगिकी, पशुधन विकास, मछली पालन, जलसंसाधन एवं आयाकट मंत्री रविन्द्र चौबे बुधवार 18 मई को दोपहर 12 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष बेमेतरा में आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों एवं अन्य विषयों पर समीक्षा बैठक लेंगे। कलेक्टर ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अद्यतन जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

सीएम 21 को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किश्त का करेंगे भुगतान

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए प्रथम किश्त की राशि का भुगतान करेंगे। इस अवसर पर सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और सभी जिला मुख्यालय मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा राशि अंतरण के कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल जिला स्तरीय कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से सम्बोधित करने के बाद किसानों के खाते में प्रथम किश्त की राशि के रूप में 1700 करोड़ रूपए का अंतरण करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिला स्तर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम के संबंध में सभी कलेक्टरों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

कलेक्टरों से कहा गया है कि राशि अंतरण के लिए जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में कृषकों एवं अतिथियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाये। कार्यक्रम के लिए गरिमा-अनुकूल स्थल चयन कर सभी आवश्यक तैयारियां और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मुख्य अतिथियों की जारी सूची अनुसार मुख्य अतिथियों एवं विधायकगणों तथा जनप्रतिनिधियों को सम्मानपूर्वक इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाए। साथ ही योजना के हितग्राहियों को कार्यक्रम स्थल पर समय पर एवं सुगमता से लाने की उचित व्यवस्था तथा कार्यक्रम स्थल पर वर्चुअल प्रसारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री श्री बघेल के वर्चुअल उद्बोधन से हितग्राहियों को सीधे जोड़ने की व्यवस्था की जाए। कलेक्टरों से यह भी कहा गया है कि गर्मी के मौसम को देखते हुए कार्यक्रम स्थल पर गर्मी के बचाव के पर्याप्त उपायों के साथ पीने के पानी का उचित प्रबंध भी सुनिश्चित किया जाए। गौरतलब है कि बीते दो वर्षों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में 12 हजार 209 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत खरीफ की सभी प्रमुख फसलों एवं उद्यानिकी फसलों को शामिल किया गया है तथा इन फसलों के उत्पादक कृषकों को प्रति वर्ष 9 हजार रूपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी राशि दी जा रही है। कोदो, कुटकी, रागी उत्पादक कृषकों को भी इसका लाभ दिया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था, यदि किसान वहां धान के बदले कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान, केला, पपीता लगाता है अथवा वृक्षारोपण करता है, तो उसे प्रति एकड़ 10 हजार रूपए इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को तीन वर्षों तक इनपुट सब्सिडी दी जाएगी।

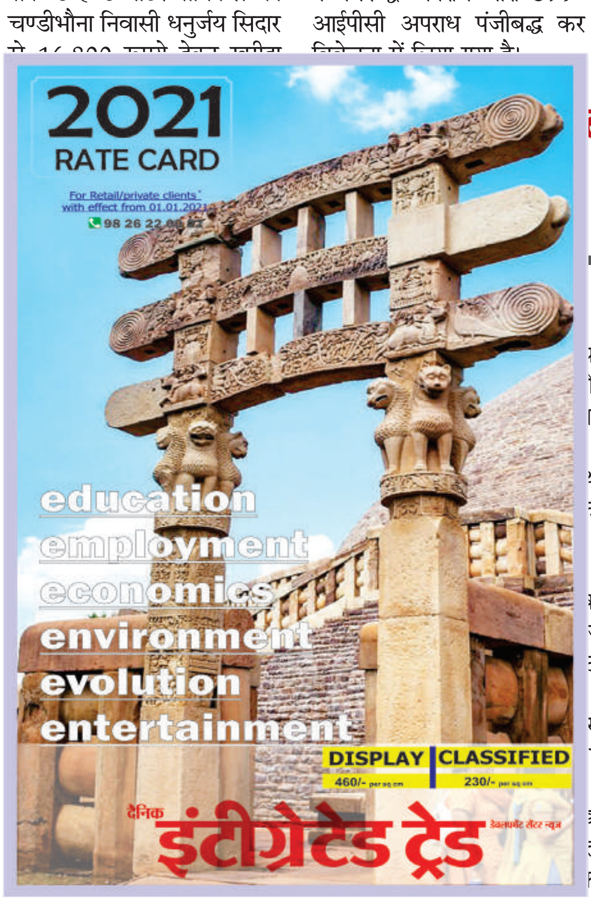

बस्तर संभाग में आज से छटवां चरण शुरू, 35 लाख से अधिक लोगों की जांच का लक्ष्य, 16 जून तक चलेगा अभियान

-साथ टीबी, मोतियाबिंद और स्केबीज की भी घर-घर जांच

...अधिकारी), मितानिनों ...शामिल किया गया है। ...आरडी किट के माध्यम से ...जा रही है। पॉजिटिव पाए ...थानीय स्तर पर उपलब्ध ...र तत्काल मलेरिया के ...का सेवन कराया जा रहा ...के आधार पर संभावित ...की जा रही है तथा इसकी ...जों की लाइन लिस्ट भी ...टीबी के संदेहास्पद मरीजों ...वालंटियर के माध्यम से ...र में करवाई जाएगी। टीबी ...जाने पर एनटीईपी अ्रहङ्क्षद्गह्लह्यश्चद्बह्य (क्रह्लश्चद्दह्लङ्कद्ब) स्टॉफ के ...त्वरित उपचार प्रारंभ किया ...के अंतर्गत मोतियाबिंद के संदेहास्पद मरीजों की जांच एवं उनके बारे में जानकारी एकत्रित कर संबंधित सुपरवाइजर के माध्यम से खंड चिकित्सा अधिकारी को दी जाएगी। स्केबीज के भी संदेहास्पद मरीजों की जांचकर तत्काल उपचार प्रदान किया जाएगा। इसके रोगियों की सूची भी तैयार की जाएगी। जांच दलों द्वारा स्केबीज बीमारी के लक्षणों का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में मलेरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित बस्तर संभाग में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के पहले पांच चरणों का व्यापक असर दिखा है। पूर्व में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के नाम से संचालित इस अभियान के प्रभाव से वहां एपीआई यानि प्रति एक हजार की आबादी में सालाना मिलने वाले मलेरिया के मरीजों की संख्या में बड़ी कमी आई है। अभियान के प्रथम चरण में जहां मलेरिया पाजिटिविटी दर 4.6 थी वह घटकर पांचवें चरण में 0.79 रह गई है।

जनवरी-फरवरी-2020 में बस्तर संभाग के सातों आकांक्षी जिलों में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान का पहला चरण संचालित किया गया था। उसी साल जून-जुलाई में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान का दूसरा चरण संचालित किया गया। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की सफलता को देखते हुए इसका तृतीय चरण दिसम्बर-2020 व जनवरी-2021 में बस्तर संभाग के साथ-साथ सरगुजा संभाग के 26 विकासखण्डों में भी संचालित किया गया। चतुर्थ चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग के साथ प्रदेश के 21 जिलों के 85 f

वकासखण्डों तक इसे विस्तारित किया गया। अभियान का पंचम चरण बस्तर संभाग के सभी सातों जिलों में संचालित किया गया। अभियान से मलेरिया उन्मूलन के साथ ही एनीमिया और कुपोषण को खत्म करने तथा शिशु व मातृ मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिल रही है। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के पहले चरण में बस्तर संभाग में घर-घर जाकर 14 लाख छह हजार, दूसरे चरण में 23 लाख 75 हजार, तीसरे चरण में 15 लाख 70 हजार, चौथे चरण में 19 लाख 98 हजार एवं पांचवें चरण में 14 लाख 36 हजार लोगों की मलेरिया जांच की गई है।

संपादकीय

आतंकी मंसूबे

कश्मीर घाटी में एक बार फिर पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। कई सालों से उन्हें घाटी में बसाने के प्रयास चल रहे थे, इसमें कुछ कामयाबी भी मिलने लगी थी, मगर अब इसकी उम्मीद धुंधली पड़ने लगी है। बडगाम के चडूरा तहसील कार्यालय में घुस कर जिस तरह दहशतगर्दों ने एक कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी, उससे स्वाभाविक ही वहां के लोगों में रोष बढ़ा है।इससे एक बार फिर पंडितों के घाटी छोड़ने को लेकर चिंता पैदा हो गई है। ताजा घटना की जिम्मेदारी जिस कश्मीर टाइगर्स नामक संगठन ने ली है, वह बिल्कुल नया जान पड़ता है। यानी अब वहां दहशतगर्दों के नए संगठन बन रहे हैं या पुराने संगठन नए नामों से सक्रिय हो गए हैं।इस घटना से यह भी जाहिर है कि इस संगठन का निशाना खासतौर से कश्मीरी पंडित हैं। हालांकि लंबे समय से वहां सुरक्षाबलों की तैनाती बढ़ी है, खुफिया एजेंसियां सक्रिय रहती हैं और सेना के तलाशी अभियान निरंतर चलते हैं, उसके बावजूद दहशतगर्दी पर नकेल नहीं कसी जा रही, वे नए नामों से सिर उठाने लगे हैं, तो इससे यही रेखांकित होता है कि इस दिशा में नए ढंग से रणनीति बनाने की जरूरत है।बडगाम की ताजा घटना अकेली नहीं है। पिछले साल इसी तरह एक दवा विक्रेता कश्मीरी पंडित की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। उसका परिवार शुरू से घाटी में ही रह रहा था। पिछले महीने भी एक कश्मीरी पंडित की इसी तरह हत्या कर दी गई। पिछले सात सालों में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। इसके पहले कश्मीरी पंडितों की हत्या का सिलसिला रुक गया था और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय विस्थापित पंडितों को दुबारा घाटी में लौटाने और बसाने का अभियान चला था।घाटी के मुसलमान भी चाहते थे कि वे लौट कर अपनी जगह-जमीन पर फिर से कब्जा लें। मगर कुछ सालों से, खासकर जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त होने के बाद जिस तरह की कटुता वहां पैदा हुई है, उसकी प्रतिक्रिया में भी पंडितों की हत्या हो रही है। पिछले दिनों घाटी से पंडितों के पलायन को लेकर एक फिल्म आई, तो उस पर देश भर में चर्चा हुई।उसे लेकर एक बार फिर कश्मीरी पंडितों के हक की मांग कुछ तीखे स्वर में उठने लगी। ऐसे में स्वाभाविक रूप से घाटी के अलगाववादी संगठनों की भी कड़ी निंदा हुई। इसकी प्रतिक्रिया भी इन नई घटनाओं के रूप में देखी जा सकती है। कश्मीरी पंडितों को घाटी में फिर से बसाने के लिए उन्हें सरकारी नौकरियों में जगह सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया।इस तरह कई विस्थापित पंडितों को वहां नौकरियां मिलीं और वे अपने पैतृक घरों को सुधार कर रहने लगे। बडगाम में जिस युवक की हत्या कर दी गई, वह भी इसी योजना के तहत वहां रहने गया था। अब इस घटना से वहां इस तरह वापस गए लोगों में दहशत पैदा होना स्वाभाविक है।इसलिए सरकार की जवाबदेही को लेकर सवाल उठने लगे हैं। केवल नौकरी देने और विस्थापितों को कश्मीर में वापस लौटाने की कोशिश से इस दिशा में कामयाबी नहीं मिलेगी। उनकी सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम करने होंगे। जब तक वे सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, भला कब तक वहां टिके रह सकेंगे। हैरानी की बात है कि तहसीलदार के कार्यालय में घुस कर कैसे वहां काम कर रहे युवक को गोली मार कर आतंकी आसानी से निकल गए।

पाकिस्तान, लोकतंत्र और आती-जाती सरकारें

(डॉ. मनन द्विवेदी, शोणित नयन)

भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों की कोलाहल इस बुनियाद पर टिकी हुई है, कि देश में अराजक, अंधव्यवस्थात्मक और राजनीतिक रूप से अस्थिर स्थिति के कारण पाकिस्तान एक विफल राज्य है। पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, हालांकि वह एक मात्र क्रिकेट आइकन से एक गंभीर राजनीतिक नेता बनने के लिए परिवर्तित हो गए, 2019 की अपनी घोषणा को पूरा नहीं कर सके, मैं आपके लिए विश्व कप लाऊंगा। इमरान खान की विदेश नीति और कूटनीति के सिद्धांतों में बदलाव के मद्देनज़र, पाकिस्तान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के पद से किसी चमत्कार के उभरने की उम्मीद करना मूर्खता होगी। शहबाज शरीफ को एक महामारी की चपेट में आई अर्थव्यवस्था विरासत में मिली है, और पाक राष्ट्र के लिए उनकी पहली प्रतिक्रिया कि- वह पाकिस्तान को निवेश के लिए स्वर्ग में बदल देंगे, निवर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा की गई भूलों के आलोक में कुछ अधिक ही रसीले लगते हैं।

ड्रैगन फोर्स के शातिर गरीबी जाल नेटवर्क में पाकिस्तान

चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) के भू-आर्थिक और भू-राजनीतिक उपकरणों और बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से चीन के साथ गठजोड़ और साझेदारी ने पहले ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, और इसे एक कर्जदार राष्ट्र में बदल दिया है, जो बड़े पैमाने पर चीनी जनवादी गणराज्य के कुलीन व्यापारिक हितों के स्वामित्व में है। इसके अलावा, भारत को इमरान खान शासन के बाद से कुछ भी ज्यादा उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय विदेश नीति व्यवस्था की हार्दिक प्रशंसा को ध्यान में रखते हुए वाशिंगटन और क्रेमलिन के बीच एक सफल, लेकिन बहुत कठिन तंग रस्सी की सैर करके की। ऐसा करके, उन्होंने पाकिस्तान में घरेलू व्यवस्था का गुस्सा अर्जित किया, और बाकी राजनीतिक विपक्ष को आलोचना के हथियार प्रदान किए।

इमरान खान के बदलते तेवर

लोग उन्हें भारत समर्थक प्रधानमंत्री के रूप में मानने लगे, जो नई दिल्ली पर काफी हद तक नरम थे, जो कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में आधिकारिक तौर पर मानने के लिए एक राजनीतिक रूप से गलत मुद्रा है। शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली नई व्यवस्था से किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पाकिस्तान के संबंधों को भी तत्काल सुधार की आवश्यकता है।

हालांकि, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से पाकिस्तान ने बड़े दक्षिण एशिया में एक फ्रंट लाइन स्टेट के विशेषाधिकार प्राप्त कद का आनंद लिया है, फिर भी पाकिस्तान के साथ अफगान पड़ोस में भारत की घुसपैठ का परिदृश्य थोड़ा अलग है। पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा अलग-थलग कर दिया गया था, और जब प्रधान मंत्री इमरान खान ने अमेरिकी भूमिका और सहायता देने के लिए बड़ी पश्चिमी भूमिका के बारे में अमेरिका का प्रचार करना शुरू किया और अफगानिस्तान के राष्ट्र राज्य में बढ़ती मानवीय आपदा से तत्काल निपटने के लिए। अमेरिकी पाकिस्तानी संबंधों को भी एक सुधार की जरूरत है, और प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ को एक असफल और सीमावर्ती राज्य की समझ से परे जाने की जरूरत है, ताकि राज्यों के बड़े इस्लामी समुदाय और बड़ी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में पाकिस्तान का कद बढ़ाया जा सके।

शहबाज शरीफ सरकार के कठिन कूटनीतिक क्षेत्र

शहबाज शरीफ सरकार पाकिस्तान की अच्छी तरह से सेवा कर रही होगी यदि वह ऋण और सहायता के लिए विश्व बैंक और आईएमएफ से संपर्क करे और पाकिस्तान की जर्जर अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार लाने का प्रयास करे। इसके अलावा, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) और बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से चीन को बेचने पर विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा अफ्रीका के असफल ऋणी राज्यों को चीनी भागीदारी के साथ चलने के परिणाम कोने के आसपास हो सकते हैं। इस प्रकार, इमरान खान के बाद की सरकार केवल बात करने में सक्षम हो सकती है क्योंकि ऊर्जा और भू-आर्थिक परिदृश्यों में क्षेत्रीय और वैश्विक अशांति के लिए दक्षिण एशियाई राज्य द्वारा एक सहकारी अधिनियम की आवश्यकता होती है, लेकिन पाकिस्तान की विदेश नीति का एकमात्र प्रमुख स्तंभ एक पर आधारित है। भारत विरोधी दृष्टिकोण, गार्ड में बदलाव के साथ बहुत अधिक बदलाव की उम्मीद नहीं है।

संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बीच सत्ता संघर्ष में पाकिस्तान एक प्रमुख क्षेत्रीय टुकड़ा है। इस्लामाबाद में नई सरकार से निपटने में नई दिल्ली की कोई भी रणनीति पाकिस्तान के इमरान के बाद के राजनीतिक प्रक्षेपवक्र के आकलन पर निर्भर करेगी। इस पहेली में, दो महत्वपूर्ण कारक सामने आते हैं- पहला पाकिस्तान में नागरिक-सैन्य संबंधों की बदलती प्रकृति है, और दूसरा गहराते आर्थिक संकट और सामाजिक अंतर्विरोधों के कारण पाकिस्तान की राजनीति की बढ़ती नाजुकता है।

पाकिस्तान के लिए भारत क्यों मायने रखता है?

नई इस्लामाबाद सरकार के लिए भारत को शामिल करना उच्च प्राथमिकता होने की संभावना नहीं है। जैसा कि, इसकी तनाव प्लेट पर कई अन्य चीजें लगातार बनी हुई हैं, जैसे कि इसके ध्वजांकित आर्थिक भाग्य के लिए पुनरुद्धार रणनीति, अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा का स्थिरीकरण, और ईरान, यूएई, सऊदी अरब, और तुर्की सहित मध्य पूर्व के प्रमुख देशों के साथ अपने संबंधों को पुनर्संतुलित करना। परंपरागत रूप से, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री की पहली विदेश यात्रा अक्सर सऊदी अरब और चीन की होती है, इन दोनों देशों के साथ पाकिस्तान के मजबूत रणनीतिक संबंधों के कारण।

पाकिस्तान, जिसके पारंपरिक रूप से पश्चिम और चीन के साथ अच्छे संबंध थे, को अपने महान शक्ति संबंधों में संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। जहां सेना और नई सरकार अमेरिका के साथ संबंध बहाल करने के लिए उत्सुक हैं, वहीं इमरान खान ने उनके लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के लिए इमरान खान की बार-बार प्रशंसा, पाकिस्तान सेना की आलोचना थी जिसने लंबे समय से इस्लामाबाद के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को आगे बढ़ाया है।

आगे बढ़ने का रास्ता

नई दिल्ली को मौजूदा संकट के कारण पाकिस्तान के रणनीतिक रुख में संभावित बदलाव पर ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान से अच्छी खबर यह है कि भारत राजनीतिक वर्गों के बीच या इमरान खान और सेना द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए गहरे राज्य के बीच तर्क का हिस्सा नहीं है।

इसके अलावा, पाकिस्तान की हाल ही में जारी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, 2022-26, उभरते हुए वैश्विक रुझानों में पाकिस्तान का साथ देना चाहती है और नीतिगत उद्देश्यों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करती है, जहां पाकिस्तान को अपने राष्ट्रीय संसाधनों का निवेश करना चाहिए ताकि सबसे अधिक लाभकारी परिणाम सुनिश्चित हो सकें। इस नीति दस्तावेज के सिद्धांतों के तहत, पाकिस्तान देश और विदेश में शांति की अपनी नीति के तहत भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहता है। और एक व्यापक रूपरेखा में, यह नीति दस्तावेज निर्देशित करता है- एक संतुलित और पर्याप्त रूप से संसाधन वाली विदेश नीति, जो राजनीतिक और आर्थिक कूटनीति के माध्यम से राष्ट्रीय हितों की रक्षा और उन्हें आगे बढ़ाते हुए संघर्षों को कम करती है। एक भारत जो पाकिस्तान की बदलती भू-राजनीति की सटीक समझ रखता है, वह इस्लामाबाद से बेहतर तरीके से निपटने में सक्षम होगा।(डॉ. मनन, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में अंतराष्ट्रीय संबंध और अंतराष्ट्रीय संगठन के सहायक प्रोफेसर हैं। शोणित नयन, इंडिया स्मार्ट सिटीज मिशन, में फेलो के रूप में कार्यरत हैं। यहां व्यक्त किए गए विचार निजी हैं।)

मोदी की अजेयता का रहस्य

(शशि शेखर)

मैंने उन्हें पहली बार नजदीक से 24 जनवरी, 1992 को देखा था। वह जम्मू में पत्रकारों से अनौपचारिक बात कर रहे थे। मुझे उनकी दृढ़ता, साफगोई और सटीक शब्दों के चयन ने प्रभावित किया था। उन दिनों वह 'महज' गुजरात, यानी एक प्रादेशिक इकाई के महासचिव थे, पर उनकी उपस्थिति सबसे बड़े नेताओं के बीच दर्ज थी। वह नरेंद्र मोदी थे, मौजूदा प्रधानमंत्री।

इससे पहले नरेंद्र मोदी का नाम लालकृष्ण आडवाणी की 'राम-रथयात्रा' के दौरान चर्चा में आया था। इस बार वह पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी की कन्याकुमारी से कश्मीर के श्रीनगर स्थित लाल चौक तक की 'एकता यात्रा' के संयोजक थे। बताने की जरूरत नहीं, ये दोनों यात्राएं आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्तादायी जड़ी-बूटी साबित हुईं।जम्मू से लौटने के बाद भी मन के एक कोने में उनकी छाप बनी रही। करीब 10 साल बाद उनका नाम अचानक फिर सुर्खियों में आया। इस बार भाजपा आलाकमान ने उन्हें केशुभाई पटेल की जगह गुजरात का मुख्यमंत्री चुना था। 26 जनवरी, 2001 को आया जलजला केशुभाई के शासन की कलई खोल गया था। जिस दिन यह खबर आई, मेरे चैनल के सहयोगियों में चर्चा महज यह थी कि मोदी अभी तक किसी सरकारी पद पर नहीं रहे हैं। इस विकट वक्त में उन्हें मुख्यमंत्री का दायित्व देकर उनका भला किया गया है या बुरा? उन दिनों केशुभाई का कद बहुत बड़ा था। अंग्रेजी की कहावत का सहारा लें, तो नरेंद्र मोदी को उनके पांवों से बड़े जूते थमा दिए गए थे। आकलनकर्ता आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे, पर मोदी चुपचाप काम में जुटे थे।इतिहास बनाने वाली सफलताओं की शुरुआत ऐसे ही छोटे, पर सधे और सुविचारित कदमों से होती है।

अगले साल मुख्यमंत्री मोदी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे तबाह हो चुके भुज और उसके आसपास के इलाके को पुन:-मुख्यधारा में दौड़ने लायक बना दिया गया है। अगर आप आज कच्छ के रण से गुजरें, तो आपको नमक से सफेद हुई भुरभुरी बालू के बीच से गुजरती शानदार सड़कें, गांवों में बिजली के खंभे, पानी की टंकियां और अस्पताल दिखाई पड़ेंगे। यह आसान काम नहीं था, पर यदि मोदी आसान कामों में ही उलझे रहते, तो आज देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। उसी साल गुजरात में दंगे हो गए। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री वाजपेयी ने अहमदाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब 'राजधर्म' का पालन करने की नसीहत दी, तब बिना एक भी क्षण गंवाए मुख्यमंत्री मोदी अपना मुंह माइक्रोफोन के पास लाए और दृढ़ता से जवाब दिया- 'वही तो कर रहा हूं साहब'। उनके आलोचकों ने इसे 'दुस्साहस' साबित किया, पर मोदी जानते थे कि दोबारा ऐसा न हो, इसका इंतजाम उन्हीं को करना है। वह इसी मुहिम में बिना किसी शोर-शराबे के जुटे थे। यह ऐतिहासिक तथ्य है, इसके बाद नरेंद्र मोदी 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और इस दौरान एक भी दंगा नहीं हुआ। इस ऐतिहासिक तथ्य से कौन मुंह चुरा सकता है? यह तभी हो सकता था, जब कानून-व्यवस्था के अनुपालनकर्ता किसी एक वर्ग के मोह में अंधे न हों। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने कल्याणकारी राज्य की स्थापना की हरचंद कोशिश की। सरकारी सुविधा और सहायता बिना किसी भेदभाव हर वर्ग तक समान भाव से पहुंची। इससे सभी तबकों में भरोसा कायम हुआ।यह काम सरल नहीं था। इसकी शुरुआत सबसे दूर और सबसे निचली सीढ़ी पर बैठे व्यक्ति से की जानी थी। इसके लिए एक दिन उन्होंने गुजरात के मुख्य सचिव से पूछा कि आपने किस ताल्लुका से अपने करियर की शुरुआत की थी? मुख्य सचिव का जवाब मिलते ही उन्होंने तपाक से पूछा, क्या आपको मालूम है कि उस ताल्लुका की हालत कैसी है? आप तो मुख्य सचिव हो गए, पर वह ताल्लुका वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। क्यों न आप उस तहसील को गोद लेकर उसका कायाकल्प करने की कोशिश करें? मुख्य सचिव द्वारा सहमति जताते ही उन्होंने सभी सचिवों को बुलाकर इस निर्देश को दोहराया। हर सचिव के हिस्से उसका पहला ताल्लुका आया। आज गुजरात में 33 जिले हैं। हो सकता है, उस वक्त कुछ कम रहे हों, पर अंकगणित का सहारा लें, तो मुख्य सचिव सहित 40 से अधिक सचिवों ने इस तरह हर जनपद की बेहतरी में सीधा योगदान किया। मोदी आज प्रधानमंत्री हैं और इस नाते उनके प्रयोग की जमीन अब पूरा देश है। उन्होंने 112 जिलों में युवा कलक्टरों की तैनाती करवाकर उन्हें यह नेक काम सौंपा है। इन जिलों का चयन करने के लिए दो दर्जन से अधिक बिंदु बनाए गए, ताकि सर्वाधिक पिछड़े स्थानों पर विकास की किरणें सबसे पहले पहुंच सकें। यह 'अंत्योदय' नहीं, तो और क्या है?

इस विवरण से आप समझ गए होंगे कि नरेंद्र मोदी की अजेयता का रहस्य क्या है? बतौर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री वह पिछले 21 वर्षों से सत्ता-सदन में हैं। अपने आप में यह अनोखा कीर्तिमान है।अपने लंबे करियर में मुझे इंदिरा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक सभी प्रधानमंत्रियों को देखने, सुनने और समझने का मौका मिला है। सभी ने मुल्क की तरक्की में अपने-अपने हिसाब से योगदान किया, पर मुझे कहने में संकोच नहीं कि दृढ़ता और लक्ष्य के प्रति स्पष्टता का ऐसा मेल पहले मैंने कभी नहीं देखा। वह खुद गरीब परिवार में जन्मे, इसलिए गरीबी का दंश जानते हैं। संघ का कार्यकर्ता रहते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में काम करने के दौरान उन्हें समझने का मौका मिला कि सरकारी योजनाएं समूची नेकनीयती के बाद असफल क्यों हो जाती हैं? यही वजह है कि उनके फैसले संपूर्ण क्रियान्वयन के लिए होते हैं। समाज, सत्ता और व्यवस्था की गहरी समझ के कारण ही वे अब तक वर्जित रहे विषयों पर फैसले ले सके। सर्जिकल स्ट्राइक, अनुच्छेद-370, तीन तलाक, सीएए आदि इसके प्रमाण हैं। इसी महीने वह अपने कार्यकाल का आठवां साल पूरा करने जा रहे हैं। हाल में हुए पांच राज्यों के चुनावी परिणाम साबित कर चुके हैं कि सियासी तौर पर वह चुनौती विहीन हैं। अगर सामाजिक और आर्थिक मामलों की बात करें, तो प्रधानमंत्री को यकीनन कुछ मोर्चों पर जूझना होगा। पिछले कुछ महीनों से देश में कभी भाषा, तो कभी मजहब के नाम पर अजनबी और आहत कर देने वाले स्वर उभरे हैं। इसी तरह कोरोना के साथ रूस-यूक्रेन युद्ध ने आर्थिक क्षेत्र में तमाम मुसीबतें खड़ी की हैं। साल के अंत में गुजरात और हिमाचल में चुनाव भी होने हैं। जाहिर है, हर बार की तरह हर निगाह उनकी तरफ है।

जब भूखे बच्चे अकुलाते हों

(तवलीन सिंह)

आज सुबह मैं उस इमारत को देखने गई, जो तैयार होने के बाद बन जाएगी भारतीय लोकतंत्र का नया मंदिर। इस इमारत के पास जाने नहीं देते हैं लोकसभा के पहरेदार, लेकिन काफी करीब जाकर जब मैंने नए संसद भवन को देखा, तो दिखा कि जो पुरानी इमारत है संसद की, वह इतनी छोटी, इतनी बौनी दिखती है कि उसको देख कर याद करना मुश्किल होगा 'न्यू इंडिया' के बाशिंदों को कि यह बौनी, गोल इमारत वही है, जो गवाह है भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की।

इस महीने की 26 तारीख को पूरे होंगे नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के पूरे आठ वर्ष। इन आठ सालों में मोदी ने साबित किया है कि उनको बड़ी-बड़ी इमारतों का बहुत शौक है। उनके प्रवक्ता जब उनकी प्रशंसा करते हैं, तो कहना कभी नहीं भूलते कि 'विश्व का यह सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है' या 'विश्व की यह सबसे ऊंची प्रतिमा' है।

इतिहास जब इस दौर का लिखा जाएगा, तो जरूर याद किया जाएगा कि मोदी ने अपने शासनकाल में बहुत सारी विशाल इमारतें बनाई थीं और बहुत सारी विशाल योजनाओं की नींव रखी थी। लेकिन इन विशाल चीजों के बीच अपने प्रधानमंत्री जैसे भूल गए हों उन छोटी चीजों को, जो बड़ी इमारतों और योजनाओं से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। आज चलिए बात करते हैं उन 'छोटी' चीजों की।

शुरू करते हैं देश के बच्चों से। पिछले हफ्ते राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) की रिपोर्ट आई, जिसके मुताबिक नवासी फीसद भारतीय बच्चे कुपोषित हैं। एनएफएचएस का पिछला सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था 2015-16 में, जिससे पता लगा था कि भारत के 90.4 फीसद बच्चे कुपोषित थे। सो, मोदी के दौर में इतना थोड़ा परिवर्तन आया है इस गंभीर आंकड़े में कि न होने के बराबर।

कड़वे सच और भी हैं 'न्यू इंडिया' के। स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा विश्व में जरूर हुई है और मोदी की प्रशंसा भी बहुत हुई है दुनिया में इस अभियान को लेकर, लेकिन दिल्ली के एक विशाल कूड़े के पहाड़ में कई दिनों तक आग लगी रही, जिसको कोई बुझा नहीं पा रहा था, क्योंकि यह पहाड़ सत्रह मंजिला इमारत से ऊंचा है। कूड़े के इस पहाड़ पर गंदगी जलने से ऐसी जहरीली हवा आ रही थी, जो दिल्ली की अति-प्रदूषित वायु को और प्रदूषित कर रही थी। सवाल है कि हम अगर चांद तक जाने का सपना देख सकते हैं, तो क्यों नहीं दुनिया के अन्य देशों से सीख सकते हैं कूड़े को नष्ट करने के आधुनिक तरीके?

प्रधानमंत्री की नजरों में शायद यह छोटी बात होगी, लेकिन हर भारतीय गांव में मिलेंगे आपको सड़ते कूड़े के ढेर। इतनी गंदगी, इतनी मैल है भारत माता के चेहरे पर कि जितनी शायद ही किसी दूसरे देश में देखने को मिलती हो। हमसे गरीब देश भी सीख गए हैं सफाई के आधुनिक तरीके, तो हम क्यों नहीं सीख पाए हैं, बावजूद इसके कि विशेषज्ञ साबित कर चुके हैं कि भारत की तकरीबन नब्बे फीसद बीमारियां गंदगी से पैदा होती हैं। अब चलिए बात करते हैं 'ईज आफ डूइंग बिजनेस' की। मोदी सीना तान के कहते हैं कि बिजनेस करना उनके राज में इतना आसान हो गया है कि विदेशी निवेशकों को यहां आकर 'मेक इन इंडिया' करना चाहिए। पिछले हफ्ते मेरी मुलाकात हुई थी एक ऐसे व्यक्ति से, जिसका छोटा-सा कारोबार है एक्सपोर्ट का।

उसने मुझे बताया कि जीएसटी आने के बाद कस्टम्स अधिकारियों को पैसा बनाने का नया जरिया मिल गया है। उसके शब्दों में, 'हम जब अपने कागजात लेकर जाते हैं जीएसटी दफ्तर में, तो ये लोग कुछ न कुछ ढूंढ़ निकालते हैं और हमारी खेप रुक जाती है। लेकिन इस आलीशान सरकारी दफ्तर के बाहर मिलते हैं दलाल, जो हमको लेकर जाते हैं पास में एक छोटे से दफ्तर में, जहां रिश्वत तो देनी पड़ती है, लेकिन कागजात स्वीकृत हो जाते हैं।'

कुछ बड़े उद्योगपति हैं जो मोदी के राज में कामयाबी की सीढ़ियां तेजी से चढ़ पाए हैं, लेकिन ऐसा किया है उन्होंने अपनी पहुंच की वजह से, इसलिए नहीं कि बिजनेस करना आसान हो गया है भारत देश में। भ्रष्टाचार वैसे का वैसा है जैसे सोनिया-मनमोहन के राज में था। उदाहरण पिछले सप्ताह आया झारखंड से, जहां पूजा सिंघल नाम की एक आइएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है।

उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर से सत्रह करोड़ से ज्यादा रुपए नगद में मिले हैं। मुंबई में रहती हूं, सो अक्सर मिलती रहती हूं उद्योग जगत के लोगों से और आज तक ऐसा बंदा नहीं मिला, जिसने कहा कि भ्रष्टाचार कम हुआ है मोदी के राज में या बिजनेस करना आसान हुआ है।

पैतृक संपत्ति और स्त्री

पितृसत्तात्मक व्यवस्था वाले इस देश में स्त्री क्षमता को नजरअंदाज करने और उनके अवमूल्यन का सबसे बड़ा कारण है लड़की का पैतृक संपत्ति से बेदखल होना। आर्थिक रूप से पराश्रित औरत की स्वतंत्र सामाजिक हैसियत लगभग न के बराबर रही। मां, बहन, बेटी जैसे संबोधनों से नवाजी गई औरत का अपना नाम और पहचान ही सदैव गौण रहा है। कई स्तरों पर उसे पुरुष की जरूरतों की पूर्ति के साधन मात्र के रूप में देखा जाता रहा है। औरतों के वजूद को पुरुषों में ही समाहित माना गया। ऐसे में एक अनाम से इंसान के नाम किसी प्रकार की संपत्ति किए जाने की बात सामाज के नियंताओं ने सोची ही नहीं। इस प्रकार औरत को संपत्ति से बेदखल करने के लिखित, अलिखित सामाजिक नियम और परंपराएं भी बनती गईं। देश की आजादी के बाद भी एक लंबे अंतराल तक यही स्थिति बनी रही।

(संगीता सहाय)

आज जब स्त्रियां हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत साबित कर रही हैं, उनकी सफलता को कम आंकने, उनके जीवन को बांधने और सपनों को कतरने की पारिवारिक और सामाजिक कोशिशें भी होती रहती हैं। देश में लैंगिक समानता के तमाम दावों के बावजूद आज भी देश की महिला आबादी का बड़ा हिस्सा दोयम दर्जे की जिंदगी जीने को मजबूर है। स्त्रियों को अपने सहज, स्वाभाविक अधिकार हासिल करने के लिए भी बड़ी चुनौतियों का सामना पड़ता है।

पितृसत्तात्मक व्यवस्था वाले इस देश में स्त्री क्षमता को नजरअंदाज करने और उनके अवमूल्यन का सबसे बड़ा कारण है लड़की का पैतृक संपत्ति से बेदखल होना। आर्थिक रूप से पराश्रित औरत की स्वतंत्र सामाजिक हैसियत लगभग न के बराबर रही। मां, बहन, बेटी जैसे संबोधनों से नवाजी गई औरत का अपना नाम और पहचान ही सदैव गौण रहा है। कई स्तरों पर उसे पुरुष की जरूरतों की पूर्ति के साधन मात्र के रूप में देखा जाता रहा है।

औरतों के वजूद को पुरुषों में ही समाहित माना गया। ऐसे में एक अनाम से इंसान के नाम किसी प्रकार की संपत्ति किए जाने की बात सामाज के नियंताओं ने सोची ही नहीं। इस प्रकार औरत को संपत्ति से बेदखल करने के लिखित, अलिखित सामाजिक नियम और परंपराएं भी बनती गईं। देश की आजादी के बाद भी एक लंबे अंतराल तक यही स्थिति बनी रही।

आज यद्यपि स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में कानूनी अधिकार मिल गया है, पर गौरतलब है कि इस कानूनी बदलाव को समाज ने कितना अपनाया है? क्या बेटियों को उनका वाजिब हक मिल रहा है? उत्तर सिर्फ ना है। आज भी लगभग पुराने नियमों को ही निभाया जा रहा है। इस आधुनिक भारतीय व्यवस्था में भी लगभग पूरा समाज पूर्व से चली आ रही बनी-बनाई परंपराओं के सख्त खोल में गर्दन घुसाए, चुप्पी साधे पूर्ववत चल रहा है।

गौरतलब है कि औरत के कमजोर सामाजिक स्थिति का सबसे बड़ा कारण उसका पैतृक संपत्ति के हक से वंचित होना है। पिता की संपत्ति में बेटी के बराबरी के हकों को सारे नियम-कानून के बावजूद लोप किया जाना बड़ी स्पष्टता से स्त्री के प्रति समाज के दोहरे रवैए की कहानी कहता है।

कानून की मिताक्षरा धारा को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के रूप में संहिताबद्ध किया गया। इसमें कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में केवल पुरुषों को मान्यता दी गई। यह उन सब पर लागू हुआ, जो धर्म से मुसलिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं थे। बौद्ध, सिख, जैन, आर्यसमाज और ब्रह्मसमाज के अनुयायियों को इस कानून के तहत हिंदू ही माना गया।

पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर ही बेटी के हिस्से को लेकर आजादी के बाद से ही बहस चलती रही है। इस संबंध में लगातार सामाजिक और राजनीतिक बहसों और मांगों के बाद वर्ष 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन किया गया और बेटियों को पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार दिया गया।

मगर साथ ही उसमें यह भी जोड़ दिया गया कि अगर पिता की मृत्यु 9 दिसंबर, 2005 से पहले हो गई हो, तब बेटी को अधिकार नहीं मिल सकेगा। कहा जा सकता है कि वह कानून आधा-अधूरा ही था।

11 अगस्त, 2020 सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, 2005 की पुनर्व्याख्या करते हुए एक बार फिर समाज में चेतना लाने का प्रयास किया, जो ऐतिहासिक कानून के बाद भी जड़हीन होकर पुरातन मान्यताओं के मुगालते में जी रहा था।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में पुरुष उत्तराधिकारियों के समान हिंदू महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार और सहायक अधिकार का विस्तार किया। इस निर्णय के अनुसार, एक हिंदू महिला को पैतृक संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकारी होने का अधिकार जन्म से प्राप्त है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसका पिता जीवित है या नहीं।

यह निर्णय संयुक्त हिंदू परिवारों के साथ-साथ बौद्ध, सिख, जैन, आर्यसमाज और ब्रह्मसमाज से संबंधित समुदायों पर भी लागू है। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को यह भी दिशा-निर्देश दिया कि छह माह के भीतर इन विषयों से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाए।

पर यह अफसोसनाक है कि कानून के इस ऐतिहासिक बदलाव के बावजूद यथार्थ में स्थितियां न के बराबर बदली हैं। इसे अमली जामा पहनाने वाला हमारा समाज ऐसा चाहता ही नहीं है। लोग कानून की बातों को किताबों तक सीमित रख कर इस संदर्भ में चुप्पी साधे बैठे हैं। वे चाहते हैं कि जो जैसा है, उसी रूप में चलता रहे, क्योंकि इसी में पितृसत्तावादी समाज की भलाई है। औरतें भी इस बनी-बनाई व्यवस्था का अंग बन कर मौन हैं। वे या तो कानूनी बातों को जानती ही नहीं या अगर जानती भी हैं, तो हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा को तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहीं। उनके अंदर इस बात का भय भी है कि अगर वे अपने हक की मांग करती हैं, तो उनका परिवार छूट जाएगा। समाज में वे अकेली पड़ जाएंगी। वास्तव में पैतृक संपत्ति पर स्त्री के हक संबंधी लड़ाई कानूनी से ज्यादा मानसिक और सामाजिक लड़ाई है। इस संदर्भ में जहां पूरा समाज पुरुष के साथ खड़ा है, वहीं औरत सिर्फ कानून के कुछ पन्ने लिए इस रणक्षेत्र में नितांत अकेली खड़ी है।

पिता की संपत्ति पर सिर्फ बेटे के अधिकार की बात समाज के तहों में समाया है। आवश्यकता है, इन जड़ तहों को खरोंचने, उन्हें धो-पोंछ कर हटाने की। इसके लिए समाज के उस हर व्यक्ति को आगे आना होगा, जो अपनी पुत्री को पुत्र के समान मानने और उसे आगे बढ़ाने का दावा करता है। संभव है शुरू में चंद लोग ही सामने आएंगे, पर ये थोड़े से लोग ही इस राह को आगे के लिए मुफीद बनाएंगे।

संपत्ति के मामले में अधिकारहीन और आर्थिक मोर्चे पर दूसरों पर निर्भर रहने के कारण कितनी ही औरतों को असहनीय परिस्थितियों में जीना पड़ता है। अक्सर यह देखने में आता है कि माता-पिता की मृत्यु के बाद अविवाहित बेटियों का अपने ही घर में जीना दूभर हो जाता है। विवाहित बेटियां तो शादी के बाद अपने ही घर में मेहमान घोषित कर दी जाती हैं। किसी विपत्ति के बाद जब वे अपने उस घर में आसरा चाहती हैं, तो अक्सर उन्हें अवमानना और दुत्कार ही मिलता है। अधिकांश विवाहिताओं के दहेज हत्या या ससुराल पक्ष से प्रताड़ित होकर किए जाने वाले आत्महत्या का बीज भी इसी में छिपा होता है। 'बेटी जहां जन्म लेती है, वहां की मेहमान होती है' या 'स्वभाग्यशाली स्त्री वही होती है, जिसकी डोली जहां जाए अर्थी वहीं से उठे' जैसी बातें लड़कियों को घुट्टी के रूप में पिलाई जाती हैं। ऐसे में पैतृक संपत्ति पर अपने अधिकार की बात वे सोच ही नहीं पातीं। वास्तव में स्त्रियों की आर्थिक निर्भरता की लड़ाई मानसिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर है। इसमें उनकी जीत के लिए आवश्यक है कि कानून-व्यवस्था, समाज और परिवार सभी स्तरों पर काम हो।

दिशा के अनुसार चुनें घर की साज सज्जा एवं रंग-रोगन

क्या आप अपने नए घर को पेंट करवाने का सोच रहे हैं? या अपने पुराने आशियाने को ही नई रंगत देकर नया लुक देना चाहते हैं? यदि हां, तो आपकी घर की दीवारों को पेंट करवाने से पहले ये जरूर जान लीजिए कि किन रंगों से महकेगा आपका आशियाना। घर की साज-सज्जा एवं रंग-रोगन के लिए दिशा के अनुसार चुनें इन 5 समृद्धिदायक रंगों को, और पाएं वर्ष भर खुशहाली व सुख-समृद्धि। जानें कैसे करें रंगों का चुनाव...

घर में सुख शांति और प्रसन्नता का वातावरण बना रहे इसलिए कई लोग घर की साज–सज्जा व रंगाई के लिए वास्तु और फेंगशुई के टिप्स भी आजमाते हैं।

- घर का बैठक कक्ष सबसे अहम होता है, इसलिए यहां की दीवारों पर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत होती है। यहां पर भूरा, गुलाबी, सफेद या क्रीम कलर सबसे अच्छा माना जाता है। यहां पर इन रंगों के परदे या तकिए कवर का इस्तेमाल भी शुभ फल देता है।
- भोजन कक्ष को रंगवाते समय आसमानी, हल्का हरा व गुलाबी रंग करवा सकते हैं। इससे हमेशा ऊर्जा व ताजगी का संचार होता है और सकारात्मकता बनी रहती है।
- रसोई घर में सफेद रंग हमेशा अच्छा माना जाता है। हांलांकि यह गंदा भी बहुत जल्दी होता है, लेकिन अगर आप नियमित तौर पर सफाई बनाएं रखें तो यह बहुत ही सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है।
- बाथरूम या शौचालय के लिए हल्का गुलाबी या फिर सफेद रंग ही सबसे बेहतर होते हैं। खास तौर से बाथरूम में गुलाबी रंग का प्रयोग ताजगी बनाए रखता है और आप आंतरिक खुशी महसूस करते हैं।
- शयन कक्ष भी काफी महत्वपूर्ण होता है, यहां पर भी आप हल्का हरा, आसमानी, गुलाबी जैसे रंगों को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें देखकर मन हमेशा प्रसन्न रहे। इससे आपके रिश्तों में भी मधुरता आती है।
- पीला रंग सुकून व रोशनी देने वाला रंग होता है। घर के ड्राइंग रूम, ऑफिस आदि की दीवारों पर यदि आप पीला रंग करवाते हैं तो वास्तु के अनुसार यह शुभ होता है।
- अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आपको अपने कमरे की उत्तरी दीवार पर हरा रंग करना चाहिए।
- आसमानी रंग जल तत्व को इंगित करता है। घर की उत्तरी दीवार को इस रंग से रंगवाना चाहिए।
- घर के खिड़की दरवाजे हमेशा गहरे रंगों से रंगवाएं। बेहतर होगा कि आप इन्हें डार्क ब्राउन रंग से रंगवाएं।
- जहां तक संभव हो सके घर को रंगवाने हेतु हमेशा हल्के रंगों का प्रयोग करें।

वेडिंग के लिए डिजाइनर आउटफिट खरीदने का है मन तो पहले इन बातों पर करें फोकस

अगर आप अपनी शादी को खास बनाने के लिए डिजाइनर आउटफिट खरीदना चाहती हैं तो किसी भी आउटफिट को सलेक्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए।

लड़कियां चाहे कितना भी पैसों की बचत करना चाहें, लेकिन जब बात उनकी शादी की होती है तो वह पैसों की बचत को दरकिनार कर हर चीज बेस्ट चाहती हैं। इसमें सबसे पहले नंबर आता है उनके वेडिंग आउटफिट का। शादी के दिन हर किसी की निगाहें दुल्हन पर होती है और ऐसे में वह अपने लुक को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं कर सकतीं। यूं तो आपको कई तरह के फैशनेबल वेडिंग लहंगे आदि मिल जाएंगे, लेकिन एक एलीगेंट और ग्रेसफुल लुक पाने के लिए एक डिजाइनर वेडिंग आउटफिट खरीदना अच्छा आईडिया है। यह थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन इस तरह के डिजाइनर आउटफिट में अलग–अलग कलर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, उसकी आर्टिस्टिक एंब्रायडरी और सुंदर मोटिफ व अन्य डिजाइन वेडिंग आउटफिट के बेहद खास बनाते हैं। हो सकता है कि आपने भी अपनी शादी के लिए एक डिजाइनर लहंगा लेने का मन बनाया हो, लेकिन किसी भी आउटफिट को खरीदने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में

जरूर करें रिसर्च

जब आप एक डिजाइनर वेडिंग आउटफिट खरीद रही हैं तो पहले कुछ रिसर्च करनी जरूरी है। मसलन, आप अपने वेडिंग डे के दिन किस तरह का लुक चाहती हैं और फिर आप अलग–अलग डिजाइनर के वेडिंग लहंगों पर नजर डालें। इससे आपको यह समझ में आएगा कि कौन से डिजाइनर के आउटफिट आपके बजट में आपकी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। इसके अलावा, आप किसी भी डिजाइनर आउटफिट को सलेक्ट करने से पहले उसे पहनकर जरूर देखें। इससे आपको अपने फाइनल लुक का काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा।

डिजाइनर से ही खरीदें

अगर आप एक डिजाइनर वेडिंग आउटफिट खरीद रही हैं तो कोशिश करें कि आप इसे सीधे डिजाइनर से ही खरीदें। आजकल अलग–अलग ब्रांड और डिजाइनर्स के स्टोर्स अवेलेबल हैं। जहां से आपको सही पीस चुनने में आसानी होगी। लेकिन अगर आप इसे रिसेलर या फिर ऑनलाइन शॉप कर रही हैं तो आपको मैटीरियल की क्वालिटी को चेक करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप सिल्क आउटफिट खरीद रही हैं तो कुछ आसान टेस्ट के जरिए पहचान सकती हैं कि वह असली है या नकली। आप इसे अपने हाथों से रगड़ें। यदि आप गर्मी महसूस करती हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं। सिंथेटिक कपड़े के साथ गर्मी को महसूस करना लगभग असंभव है।

अगर खरीदें ऑनलाइन

अगर आप अपने डिजाइनर वेडिंग आउटफिट को किसी कारणवश ऑनलाइन आर्डर कर रह हैं जो इसके बारे में अधिकतम जानकारी प्राप्त कर लें। मसलन, आउटफिट बनाने और इसे आप तक पहुंचाने में लगने वाले समय को पहले ही जान लें। इसके अलावा, जिस ऑनलाइन स्टोर से आप आउटफिट खरीद रहे हैं, उसकी रिटर्न पॉलिसी को चेक करना न भूलें। कभी–कभी, जो आप ऑनलाइन खरीदते हैं, वह अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है। ऐसे में नो रिटर्न पॉलिसी आपके लिए मुश्किले खड़ी कर सकती हैं।

बढ़ते बचपन के साथ व्यावहारिक समझ विकसित करती हैं बेटियां

बेटियां अपने बढ़ते बचपन के साथ-साथ घर की जिम्मेदारियों और व्यावहारिक समझ को विकसित करती हैं

सिर्फ ग्यारह साल की है मेरी बिटिया। पांचवी में पढ़ती है। यूनिटरी फैमिली में एक बच्चे को क्या–क्या झेलना पड़ता है, इसका ज्वलंत उदाहरण है वह। मैं और मेरी पत्नी दोनों ही कामकाजी हैं। हमने खुद से जद्दोजहद करते, बिना किसी के सपोर्ट के जीवन जीना सीखा है और परिवार के बुजुर्गों की परवरिश से दूर मेरी बेटी ने भी खुद ही सबकुछ सीख लिया। जब वह डेढ़ साल की थी, तभी से मछली का कांटा निकाल कर खुद खाती थी। हम कामकाज में व्यस्त रहते और वह कांटा निकालने की तरकीब ढूंढ़ती रहती। यह उसने अंतत: सीख ही लिया। किसी दिन उसकी मां को एक्जाम ड्यूटी के लिए रविवार के दिन सुबह आठ बजे ही निकलना होता। कभी–कभी मुझे भी कालेज में कक्षाएं लेने पत्नी के साथ ही आठ बजे निकलना होता है। उस वक्त बेटी की आंखों में यह सवाल होता है कि तुम दोनों शाम तक लौटोगे, तो मैं दिनभर क्या करूंगी, अकेली कैसे रहूंगी। पर वह बोलती कुछ नहीं। उसकी आंखों में हठात एक सूनापन सा आता है और आकर चला जाता है। वह तपाक से कहती है। तुमलोग जाओ। दरवाजे में बाहर से ताला लगा देना। मैं अंदर से कुंडी बंद कर दूंगी और टीवी देखती रहूंगी। ऐसा कई बार हुआ है कि हम दोनों आठ–दस घंटे बाहर होते हैं और बेटी ने दिनभर टीवी देखते हुए, बाहर से ताला लगे बंद कमरे में खुद को अकेली बिताया है। जाते वक्त हम उसका खाना, बिस्किट वगैरह रख देते हैं। हिदायत देते हैं– बेटा आग के पास मत जाना, गैस मत खोलना। बिजली कट जाये, तो बिजली आने का इंतजार करना–माचिस मत जलाना। बेटी ठीक वैसा ही करती है। आज तक उसने वैसा ही किया है। यह सिलसिला पिछले चार–पांच सालों से चल रहा है। जब वह पांच–छह साल की थी, तब से। हम दिनभर अपने काम के साथ बेटी की चिंताओं में घुलते रहते हैं कि पता नहीं वह कैसी होगी। शाम को जब दरवाजे का ताला आकर खोलते हैं, तो कभी वह अपना होंमवर्क कर रही होती है। उसने घर के अंदर, बंद ताले में खुद को सेफ रखने के लिए सभी उपाय सीख लिए हैं। जैसे ही वह बाहर कोई आहट सुनती है, टीवी धीमा कर देती है। कोई आवाज नहीं निकालती। वह धीरे–धीरे बड़ी हो रही है। फिजिकली। मेंटली वह समय से पहले ही बड़ी हो गयी है। यह सब उसे कुछ हमने सिखाया है, तो कुछ परिस्थितियों ने। अपनी कई मुश्किलें वह अपनी मां के साथ शेयर करती है, तो लगता है कि इसने अपना बचपना थोड़ा खोया, थोड़ा झटका है। महज ग्यारह साल की उम्र में उसे परिस्थितियों ने परिपक्व बना दिया है। पर, वह अकेली बिटिया है। उसे जीना इसी समाज में है।

...तो रिश्ता हो जाएगा मजबूत

दुनिया में रिश्ते के बिना प्यार का अहसास ही नहीं हो सकता। रिश्ता चाहे कोई भी हो खास होता है। इसे निभाने के लिए शुरुआत भी अलग तरीके की होना चाहिए। फिर चाहे वो दोस्ती हो या फिर रिश्तेदारी।

खुशियों का अहसास अपनो से ही होता है। इसे हमेशा के लिए गहरा करने के लिए कुछ खास बातों की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि आने वाला हर पल हसीन रहे। अगर किसी कारण रिश्तों में गलतफहमियां आ भी जाए तो एक दूसरे पर यकीन इतना गहरा हो कि कोई दूसरा आपमें अपनी जगह बना न सके। लेकिन इसके लिए कुछ बातों का खास ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है ताकि प्यार से संजो कर रखा गया यह रिश्ता जिंदगी की जरूरत बन जाए।

एक दूसरे को जानना जरूरी

आप किसी से प्यार करते हैं तो इसके लिए एक बात को जान लेना बहुत जरूरी है आपको उसकी आदतों के बारे में जानना होगा। इससे आप खुद को और अपने बढ़ते रिलेशनशिप को कुछ समय दे पाएंगे। जो भविष्य में आपके लिए परेशानी नहीं बनेगा।

रिलेशनशिप से बनें पहचान

दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे दोस्ती इस तरह की हो जो आपकी पहचान बनें। इस बात का ध्यान रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोस्ती में खोते जा रहे हैं। यह बदलाव आपके लिए खतरनाक हो सकता है।

कभी शक भी जायज

जहां यकीन है वहां शक होना भी कभी कभी जायज होता है। पार्टनर पर जरूरत से भी ज्यादा यकीन कर लेने से भी कई बार रिश्ता खराब होने का डर रहता है। थोड़ा बहुत शक करना या फिर पजेसिव होने से पार्टनर को भी पता चलता है कि आप उनके लिए कितने जरूरी हैं।

एक–दूसरे को दें वक्त

एक–दूसरे के साथ समय बिता कर उसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। कई बार ज्यादा देर तक बनाई गई दूरी भी रिश्ते में खट्टास पैदा कर सकती है। ऐसे में समय की कमी के कारण अगर पार्टनर के साथ नराजगी है तो एक–दूसरे को समय जरूर दें। कहीं न कहीं आपके रिश्ते में मजबूती आनी शुरू हो जाएगी। कोशिश करें एक– दूसरे के साथ समय बिताएं।

नए–पुराने कपड़ों को इस तरह से करें टिमअप

हमसे से अधिकतर लोग ऐसे हैं, जो समय की कमी के कारण अपने वॉर्डरोब पर ध्यान नहीं दें पाते। जिसके कारण वॉर्डरोब में नए-पुराने कपड़ों का ढ़ेर लग जाता है। वक्त है, कोरोना काल का जिसमें सोशल डिस्टेंसिग का हम सभी पालन कर रहे है। जिस वजह से हम अपना ज्यादातर समय घर पर ही बिता रहे है। तो क्यों न इस समय का सही इस्तेमाल करते हुए अपने वॉर्डरोब को अपडेट किया जाएं। आइए जानते कुछ टिप्स-

- डार्क कलर के 1–2 पैंट्स अगर आपके वॉर्डरोब में हैं, तो नए लुक के लिए कुछ कलरफुल शॉर्ट कुर्ते खरीदें। कलमकारी, इकत या लखनवी चिकन के शॉर्ट कुर्ते अच्छे लगते है। साथ ही रूटीन में पहनें जानेवाले टॉप और पैंट स्टाइल को भी ब्रेक मिलता है।

- प्लेन टाइट टीशर्ट यदि आपके वॉर्डरोब में है तो इसको आप कलरफुल धोती पैंट के साथ आप टीमअप कर सकते है।
- यदि वॉर्डरोब में पुरानी प्रिटेंड सलवारों ने काफी जगह घेर रखी है, तो इनके उपर पहनने के लिए 1 से 2 कुर्ती खरीदें।
- यदि पेन्सिल जींस आपके पास हैंतो 1 से 2 फ्लोरल लॉन्ग लाइन शर्ट खरीदें।
- पुराने शॉटर्स अलनारी में है तो फिल नेक ब्लाउज टॉप या कॉन्ट्रास्ट बाइंजिंग नॉट टॉप खरीदें। नया टॉप पहनने पर पुराने शॉटर्स भी नए लुक में नजर आते है।
- अगर आपके पास कलरफुल लॉन्ग स्कर्ट है, तो उसके साथ शॉर्ट कुर्ती, टीशर्ट या लॉन्ग कुर्ते भी पहने जा सकते है।
- ए लाइन फुल लेंथ स्कर्ट पहले से है, तो उसके साथ लॉन्ग कुर्ते पहनें, हील्स पहनें। इससे हाइट अच्छी दिखगी।
- शॉर्ट स्कर्ट के साथ जैगिंग्स पहनना ट्रेंडी लुक देगा। साथ में एक्सेसरी के तौर पर स्कार्फ भी लें।

वॉर्डरोब में इन बातों का रखें ख्याल

- पैंट, जींस के लिए मल्टीपर्पस 5 लेअर हैंगर का इस्तेमाल करें। यह वॉर्डरोब की जगब को कम घेरेगा और वॉर्डरोब संवरा दिखेगा।
- सॉक्स और अंडरगारमेंट्स आर्गेनाइजर भी वॉर्डरोब को क्लीन लुक देते हैं। इसमें ब्रा का ळभी सेक्शन होना चाहिए। सिंगल पैडेड ब्रा, स्पोर्ट्स, ब्रा, टीशर्ट ब्रा, रेगलुर यूज के लिए 5 से 6 अलग–अलग ब्रा रखें। आयरन की हुई शर्ट या कुर्ते हैंगर में लटकाने से अगर जगह ज्यादा घिरती है, तो उसके लिए शर्ट ऑर्गेनाइजर अच्छा रहेगा।
- होम स्ट्रेप हैगिंग ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर वॉर्डरोब के अंदर की ओर किसी हुक पर लगाएं। इस पर अपनी चंकी ज्वेलरी, ब्रेसलेट, नेक पीस जैसी चीजें टांग सकती हैं, जिससे जरूरत के समय सामने नजर आए।

इस्लामिक देशों के संगठन को भारत की हिदायतः ओआईसी से कहा-

कश्मीर हमारा है.. उसके परिसीमन पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा न फैलाएं

नई दिल्ली

भारत ने जम्मू-कश्मीर में परिसीमन को लेकर इस्लामिक सहयोग संगठन (ह्र्रुष्ट) की टिप्पणी पर ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सोमवार को कहा- हम इस बात से निराश हैं कि ओआईसी सेक्रेट्रिएट ने एक बार फिर भारत के आंतरिक मामलों पर अनुचित टिप्पणी की है। जम्मू-कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा और अविभाज्य हिस्सा है। भारत ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि इस संगठन को किसी एक देश के इशारे पर अपना सांप्रदायिक एजेंडा फैलाने से परहेज करना चाहिए। दरअसल, ओआईसी ने जम्मू-कश्मीर में परिसीमन को लेकर भारत की आलोचना की थी, जिसके तुरंत बाद भारत ने प्रतिक्रिया दी है।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर की विधानसभा और लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर केंद्र के आयोग ने मई की शुरुआत में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी।

परिसीमन को कश्मीरियों के अधिकारों के खिलाफ बताया

इस्लामिक सहयोग संगठन ने सोमवार को ट्वीट कर जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर आपत्ति जताई। इसमे कहा गया कि भारत का यह प्रयास जम्मू कश्मीर के डेमोग्राफिक ढांचे को बदलने और कश्मीरी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन है। ओआईसी ने कहा- परिसीमन की यह प्रक्रिया चौथे जिनेवा कन्वेंशन सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्तावों और अंतरराष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन है।

1967 की अरब-इजराइल जंग के बाद मई 1971 में ओआईसी की स्थापना हुई। इसका पूरा नाम ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। इसका मकसद ही फिलिस्तीन की मदद करना और उसे इजराइल के साए से मुक्त कराना था। शुरुआत 30 देशों से हुई थी, आज 57 देश इसके सदस्य हैं। इनकी कुल मिलाकर आबादी करीब 180 करोड़ है।

अमूमन हर दौर में सऊदी अरब का ही इस पर दबदबा रहा। इसकी दो वजह हैं। पहली- मुस्लिमों की आस्था के दो सबसे बड़े केंद्र यानी मक्का और मदीना सऊदी में ही हैं। दूसरी- आर्थिक तौर पर कोई दूसरा मुस्लिम देश सऊदी के आसपास भी नहीं फटकता।

इससे पहले भी कर चुका है भारत विरोधी कमेंट

यह पहली बार नहीं है जब ओआईसी ने ऐसी टिप्पणी की है। पिछले महीने ही ओआईसी ने इस्लामाबाद में अपनी विदेश मंत्री लेवल बैठक में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष को बुलाया। इस मसले पर भी भारत ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। कुछ हफ्ते बाद ही ओआईसी ने जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। इसे लेकर ओआईसी की मीटिंग में एक रिजॉल्यूशन भी पास किया गया। संगठन ने कहा था कि जब तक कश्मीर मसला सुलझा नहीं लिया जाता, तब तक स्थायी शांति हासिल नहीं होगी। विदेश मंत्रालय ने इस रिजॉल्यूशन को बेतुका करार देते हुए कहा कि ये सभी आरोप तथ्यहीन और बेबुनियाद हैं।

1993 मुंबई धमाके के 4 आरोपी गिरफ्तार

गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद से पकड़ा; ब्लास्ट के बाद विदेश भागे फिर फर्जी पासपोर्ट से वापस आए

गुजरात

गुजरात के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी और 1993 मुंबई धमाकों के वांटेड 4 आरोपियों को अहमदाबाद से पकड़ा है। मुंबई बम धमाकों के बाद ये सभी आरोपी विदेश भागने में कामयाब रहे थे और फर्जी पासपोर्ट पर अहमदाबाद आए थे। गुजरात ॢञ्जस् ने अबू बकर, यूसुफ भटाका, शोएब बाबा और सैयद कुरैशी को पकड़ने में कामयाबी पाई है। इस संबंध में इंटेलिजेंस इनपुट मिलने पर गुजरात ॢञ्जस् ने कार्रवाई को अंजाम दिया।

अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास पकड़े गएः- ATS से मिली जानकारी के अनुसार चारों आरोपी फर्जी पासपोर्ट के जरिए एक देश से दूसरे देश में घूम रहे थे। कुछ समय पहले इन चारों के दुबई में होने का जानकारी मिली थी। चारों फर्जी पासपोर्ट के साथ अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां पहले से ही एटीएस इनका इंतजार कर रही थी।

बम प्लांट करने के साथ अन्य साजो-सामान भी जुटाए थे

आरोपियों ने 1993 के सिलसिलेवार धमाकों के लिए बम प्लांट करने के साथ ही अन्य साजो-सामान जुटाए थे। माना जा रहा है कि ये अभी भी दाऊद गैंग के संपर्क में हैं, जिसके आधार पर अब डी कंपनी के और भी कनेक्शन सामने आ सकते हैं। फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इनका अहमदाबाद आने का क्या मकसद था। आरोपियों से अब केंद्रीय एजेंसी पूछताछ करेगी।

धमाकों में 250 से अधिक लोगों की मौत हुई थी

अबू बकर, यूसुफ भटाका, शोएब बाबा और सैयद कुरैशी ने सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को गुमराह करने के लिए अपने पते बदल दिए थे। इनके पासपोर्ट में दर्ज सभी जानकारियां फर्जी निकलीं। जांच में यह सत्यापित हुआ कि ये चारों 1993 के मुंबई बम धमाकों के आरोपी हैं। इबता दें कि 12 मार्च, 1993 को शुक्रवार के दिन मुंबई में 12 सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिसमें 250 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।

कोयला तस्करी केस में ममता के भतीजे को राहत : SC ने अभिषेक-रुजिरा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई; दिल्ली की बजाय कोलकाता में पूछताछ होगी

गैर-जमानती वारंट हुआ था जारी

बंगाल

22 मार्च को ईडी ने अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी के खिलाफ पूछताछ का नोटिस जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। हालांकि, वहां उन्हें राहत नहीं मिली थी। इसी दौरान दोनों के खिलाफ पूछताछ में शामिल नहीं होने की वजह से गैर-जमानती वारंट भीजारी हो गया था। आसनसोल इलाके से बॉर्डर पार से अवैध रूप से कोयला तस्करी का मामला सामने आने के बाद सीबीआई और ईडी अलग-अलग इस मामले की जांच कर रही हैं। ईस्टर्न कोल्ड फील्ड से जुड़े अनूप मांझी की गिरफ्तारी के बाद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को भी नोटिस जारी किया गया था। ईडी के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक लिप्स एंड बाउंड प्रा.लि. और लिप्स एंड मैनेजमेंट सर्विस नामक दो कंपनियों को कोयला तस्करी के 4.37 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। यह कंपनी अभिषेक की पत्नी रुजिरा के नाम से है, इसलिए उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

3 दिन में दूसरी बार दहला पाकिस्तान : कराची में न्यू मेमन मस्जिद के पास IED ब्लास्ट से 1 महिला की मौत, 11 घायल

इस्लामाबाद

पाकिस्तान में आंतकी हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आतंकियों ने सोमवार को एक बार फिर कराची में विस्फोट किया। यहां खरादर इलाके की न्यू मेमन मस्जिद के पास हुए धमाके में एक महिला की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। कराची पुलिस का कहना है कि विस्फोट के लिए एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (ढ्ढश्वष्ठ) का इस्तेमाल किया गया था। इस हमले में पुलिस पिकअप और कुछ दूसरे वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है। अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले की निंदा की है। उन्होंने वारदात में शामिल लोगों को तुरंत पकड़ने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले लोगों से सख्ती से निपटेंगे। उन्होंने सिंध सरकार को मदद करने की बात भी कही है। इधर, सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने सभी घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सिंध के ढ्ढत्रक्क मुश्ताक अहमद महार से इस मामले की डिटेल रिपोर्ट मांगी है।

न्यूज ब्रीफ

सुनवाई का अनोखा तरीका

शादी में गए थे जज, याचिकाकर्ता की अपील पर छुट्टी के दिन वॉट्सऐप पर की सुनवाई

मद्रास। मद्रास हाई कोर्ट की एक अनोखी खबर सामने आई है। जहां जज ने वॉट्सऐप वीडियो कॉलिंग के जरिए एक मामले की सुनवाई की। जानकारी के मुताबिक, ये याचिका रविवार को दायर की गई थी। जब जज छुट्टी पर थे। अभीष्ट वरदराजा और स्वामी मंदिर के ट्रस्टी पी आर श्रीनिवासन ने प्रशासन की तरफ से रथ यात्रा को मंजूरी न दिए जाने के विरोध में एक याचिका दर्ज की थी। इस याचिका पर उन्होंने तत्काल सुनवाई की मांग की थी, जिसके बाद जज ने रविवार को ही सुनवाई की। वे एक शादी में शरीक होने गए थे, लिहाजा सुनवाई वॉट्सऐप के जरिए की गई। याचिका में कहा गया था कि हमें सोमवार को ही रथ यात्रा निकालनी है। लेकिन प्रशासन इसे रोक रहा है, अगर सोमवार को ये यात्रा नहीं निकाली गई तो गांव को देवीय प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जज को छुट्टी वाले दिन ही सुनवाई करनी पड़ी।

वॉट्सऐप वीडियो कॉल पर हुई सुनवाईः- इस मामले की सुनवाई जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने की। तब वे नागरकोइल में शादी में गए हुए थे। उस दौरान मामला तत्काल सुनवाई के लिए उनके पास पहुंचा। उन्होंने वॉट्सऐप वीडियो कॉलिंग के जरिए सुनवाई की जिसमें उनके साथ याचिकाकर्ता के वकील वी राघवाचारी और सॉलिसिटर जनरल आर षणमुगसुंदरम भी अलग-अलग जगह से जुड़े। जज ने फैसले में कहा कि हिंदू धर्म से जुड़े किसी भी कार्यक्रम को रोकने का अधिकार प्रशासन के पास नहीं है, चाहे वह रथ यात्रा हो या कोई और कार्यक्रम। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रशासन के दिए गए आदेश को खारिज कर दिया।

ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मिला शिवलिंगःकोर्ट का आदेश-

प्रशासन शिवलिंग वाली जगह को तुरंत सील करके उसे सुरक्षा में ले

वाराणसी

ज्ञानवापी से जुड़ी बड़ी खबर है। परिसर के अंदर सर्वे टीम को शिवलिंग मिला है। यह बात सामने आने के बाद वाराणसी कोर्ट ने डीएम को आदेश दिया कि जिस जगह शिवलिंग मिला है, उसे तत्काल सील कर दें। वहां पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाए। कोर्ट ने डीएम, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को यह आदेश दिया है। कोर्ट ने इन अधिकारियों को जगहों को संरक्षित और सुरक्षित रखने की व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी दी है। दरअसल, ज्ञानवापी में सर्वे के लिए तीसरे दिन टीम गई थी। बताया जा रहा है कि वहां टीम को शिवलिंग नजर आया। सर्वे टीम में शामिल हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने तुरंत वाराणसी कोर्ट में एप्लीकेशन दी। इसमें कोर्ट को बताया गया कि वहां पर शिवलिंग मिला है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। सीआरपीएफ कमांडेंट को उस जगह को सील करने का आदेश देने की मांग की गई। सीनियर डिवीजन के जज रवि कुमार दिवाकर ने तुरंत डीएम को उस जगह को सील करने का आदेश दिया है।

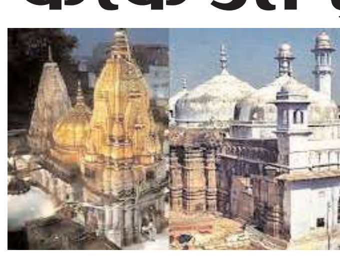

बाहर आकर हिंदू पक्ष बोला- अंदर बाबा मिल गएः- इससे पहले वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे तीसरे दिन सोमवार को पूरा हो गया। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के पैरोकार डॉ. सोहनलाल बाहर आए तो उन्होंने बड़ा दावा किया। कहा, %अंदर बाबा मिल गए... जिन खोजा तिन पाइयां। तो समझिए, जो कुछ खोजा जा रहा था, उससे कहीं अधिक मिला है। अब पश्चिमी दीवार के पास जो 75 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 15 फीट ऊंचा मलबा है, उसके सर्वे की मांग उठाएंगे।

मुस्लिम पक्ष ने कहा- फव्वारे को शिवलिंग बताया जा रहा

सर्वे करके बाहर आए मुस्लिम पक्ष के वकील ने हिंदू पक्ष के दावों का खारिज किया है। वकील ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं मिला। हम सर्वे से संतुष्ट हैं। कल, यानी 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बता दें कि एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में वादी-प्रतिवादी पक्ष के 52 लोगों की टीम सुबह 8 बजे परिसर में एंट्री की।

बच्ची के साथ यौन शोषण का मामला

डॉक्टर स्ट्रेंज की एक्ट्रेस जारा फाइथियन को 8 साल और उनके पति को 14 साल की जेल

वाशिंगटन

मार्वल सीरीज की फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज की एक्ट्रेस जारा फाइथियन और पति विक्टर मार्क को 13 साल की लड़की के यौन शोषण के आरोप लगे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जारा को नॉटिंघम क्राउन कोर्ट में यौन शोषण मामले में जूरी ने दोषी पाया है। कोर्ट ने इस मामले में उन्हें 8 साल जेल की सजा सुनाई है। जारा फाइथियन के पति विक्टर मार्क को उसी उसी नाबालिग सहित एक दूसरी लड़की के यौन शोषण के आरोप में 14 साल जेल की सजा मिली है। दोनों ने आरोपों से इनकार किया था, लेकिन जूरी ने कपल को इस मामले में आरोपी पाया और उन्हें सजा सुनाई। दोनों अब सेक्सुअल क्रिमिनल रजिस्टर पर साइन करेंगे और फिर दोनों को कभी बच्चों के साथ काम करने की अनुमति नहीं होगी।

2005-2008 तक किया था हैरेस

जारा और उनके पति विक्टर पर 2005 से 2008 के बीच एक बच्ची के साथ यौन एक्टिविटी में शामिल होने के आरोप थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, विक्टिम ने बताया कि कपल उसके साथ %डेयर% गेम खेला करते थे। विक्टिम ने कहा, %तुमने मेरी मासूमियमत छीन ली, मुझे बर्बाद किया और मुझे किसी रिलेशनशिप के लायक नहीं छोड़ा।

सजा सुन कोर्ट में रो पड़े विक्टर

सजा के लिए कपल कोर्ट में एक साथ पेश हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर के हसबैंड मार्क पब्लिक गैलरी में लोगों को देखकर रो पड़े। वहीं एक्ट्रेस एक सीट पर बैठ गईं। उन्होंने पब्लिक गैलरी में किसी की तरफ मुस्कुराते हुए वेव किया। सजा सुनाते वक्त जज मार्क वाटसन का कहना था कि जॉइंट विक्टिम के यौन शोषण की शुरुआत प्री-प्लांड थी।

डॉक्टर स्ट्रेंज में नजर आई थीं एक्ट्रेस

जारा फाइथियन ने %डॉक्टर स्ट्रेंज% में ब्रूनेट जीलोट का रोल प्ले किया था। फिल्म में एक्टर बेनेडिक्ट कम्बरबैच लीड रोल में थे। एक्ट्रेस 2022 की फिल्म एक्सीडेंट मैन-2 में भी दिखीं। वो 2020 में आई फिल्म %ट्राइबल गेट आउट अलाइव% में नजर आई थीं।

PRESS ITDC
ITDC NEWS
www.itdcindia.com

मध्य भारत से विश्वसनीय हिन्दी दैनिक समाचारपत्र
आईटीडीसी न्यूज़,

विश्वसनीयता की अपेक्षा पर सच्चा बनाने के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं,
प्रति सप्ताह आप सभी का स्तम्भ

मेरे लोग, मेरा विधान

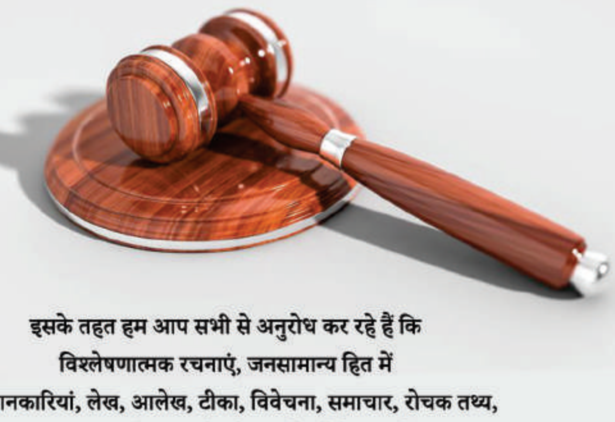

इसके तहत हम आप सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि
विश्लेषणात्मक रचनाएं, जनसामान्य हित में
नई जानकारियां, लेख, आलेख, टीका, विवेचना, समाचार, रोचक तथ्य,
नए प्रयास, अभिनव प्रयोग के रूप में हमें प्रेषित करें।

आपकी रचना, नाम, चित्र सहित, अधिकाधिक पाठकों तक पहुंचे,
इसके लिए हम, समाचार पत्र में प्रकाशित रचनाओं को,
देश के सभी प्रचलित सोशल मीडिया स्टैंड जैसे फेसबुक, लिंकेडीन, यूट्यूब, जीटॉक, टिवीटर, इंस्टाग्राम
व्हाट्सएप्प एवं हमारे डिजिटल स्टैंड से प्रचार-प्रसार भी देंगे।
(दीर्घ समय तक https://www.itdcindia.com/saga-news.php पर भी उपलब्ध)
जिससे लाभान्वित जनों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे।

आप सभी इच्छुकजन अपनी गैरमानदेय,
अपठित, नवीन, मूल एवं मौलिक रचना, हिन्दी में हमें प्रेषित करें।
(और अंग्रेजी में भेजने पर केवल हमारे डिजिटल स्टैंड पर ही प्रकाशन होगा)
उक्त हेतु, आपका चित्र, नाम, शहर, मोबाइल न, आपकी रचना, मेल करें-ईमेल
itdcnewsmp@gmail.com

मध्य भारत का विश्वसनीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
इंटीग्रेटेड ट्रेड
डेव्हेलपमेंट सेंटर न्यूज़

न्यूज़ ब्रीफ

आईपीएल में पंत का सुपर फ्लॉप शो : 13 मैच से नहीं लगा सके एक भी फिफ्टी

मुंबई। ऋषभ पंत भारत के नंबर वन विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। टीम इंडिया को उनसे टी-20 वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन की आस है। इस बीच पंत को आईपीएल 15 में कप्तानी के बोझ तले टूटते देखा जा रहा है। यकीन कर पाना मुश्किल है कि इस पॉकेट डायनामाइट ने आईपीएल के इस सीजन में एक भी 50 नहीं लगाई है। उम्मीद जताई जा रही थी कि सीजन के लास्ट फेज में कम से कम उनका बल्ला बोलेगा, लेकिन पंजाब के खिलाफ भी ऋषभ लापरवाही कर बैठे और 7 रन बनाकर चलते बने।

लिविंगस्टोन पर हावी होने के लिए पंत क्रीज से आगे तो बढ़ गए, लेकिन सही समय पर लौट नहीं सके। विकेटकीपर जितेश शर्मा ने पंत को आसानी से स्टंप कर दिया। ऋषभ पंत को यह एहसास नहीं हो पा रहा कि सिर्फ खिलाड़ी और कप्तान होने में फर्क होता है। एक प्लेयर के तौर पर आप कई बार सिचुएशन का ध्यान रखे बिना खुलकर शॉट खेलते हुए विकेट गंवा देते हैं। उस वक्त आप पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन तब रवैया बदलने के लिए कैप्टन और कोच आपको समय देते हैं। खुद कप्तान होने के नाते आपसे जिम्मेदार होने की उम्मीद की जाती है। जिस वक्त क्रीज पर कप्तान के रूप में ठहर कर टीम को बड़े स्कोर की ओर ले जाना चाहिए, पंत सबसे पहले पहले आउट होकर वापस पवेलियन की ओर चल देते हैं। जितने भी सफल कप्तान रहे हैं, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से टीम में अपनी जगह सुनिश्चित की है। आप सिर्फ कप्तान हैं, इसलिए टीम में आपकी जगह लंबे अरसे तक पक्की नहीं हो सकती। आपको परफॉर्मेंस के बलबूते अपनी जगह हासिल करनी होगी।

ओवर एग्रेशन के चक्कर में विकेट फेंक रहे हैं

पंत अति-आक्रामकता के शिकार हो रहे हैं। वह आते ही पहली बॉल से अटैक करने लगते हैं। फिर सस्ते में अपना विकेट गंवा कर चलते बनते हैं। आउट होने के बाद जिस तरह वह प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, उन जैसे दिग्गज खिलाड़ी को शोभा नहीं देता। 13 पारियों में एक भी अर्धशतक ना होना पंत जैसे दिग्गज बल्लेबाज के लिए चिंताजनक है। ऋषभ पंत के पिटारे में तमाम तरह के शॉट्स हैं। अगर वह थोड़ी देर क्रीज पर टिक जाएंगे, तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़ सकते हैं। ऋषभ को सिर्फ यह समझना है कि ओवर एग्रेसिव होकर विकेट गंवा देने की बजाय शुरुआती कुछ ओवर धीमी गति से बल्लेबाजी की जा सकती है।

छवि में कैद होकर रह गए हैं ऋषभ

ऋषभ पंत की इमेज एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज की है। फैंस को लगता है कि अगर पंत मैदान में आएगा, तो सिर्फ धमाकेदार शॉट लगाएगा। अपनी पुरानी छवि के दबाव में पंत खेलने का अंदाज नहीं बदल पा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि टॉप ऑर्डर में आते ही 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाने हैं।

रणजी क्वार्टर-फाइनल के लिए साहा और शमी बंगाल टीम में

नई दिल्ली

रणजी ट्रॉफी 2021-22 लीग चरण से बाहर होने के तीन महीने बाद ऋद्धिमान साहा छह जून से बेंगलुरु में झारखंड के ख़िलाफ़ क्वार्टर-फ़ाइनल से पहले बंगाल टीम में लौट आए हैं। बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) ने दल में तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी का भी नाम दिया है। हालांकि उनकी उपलब्धता बीसीसीआई और प्रमुख कोच राहुल द्रविड़ से उनके कार्य प्रबंधन पर बात करने के बाद पुख़्ता हो पाएगी। बंगाल टीम की कमान अभिमन्यु ईश्वरन के हाथों में होगी।

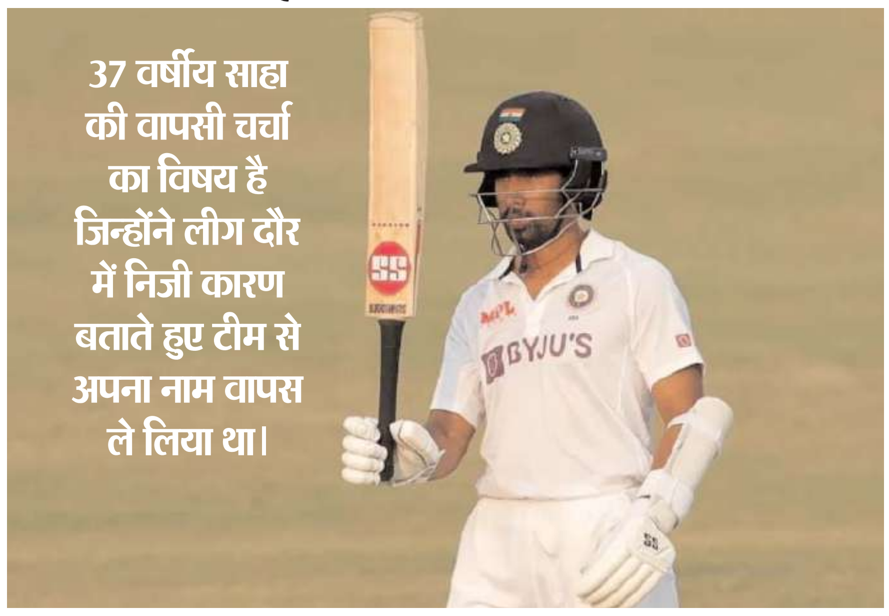

37 वर्षीय साहा की वापसी चर्चा का विषय है जिन्होंने लीग दौर में निजी कारण बताते हुए टीम से अपना नाम वापस ले लिया था। यह फ़ैसला तब आया था जब साहा को श्रीलंका के ख़िलाफ़ हुई घरेलू टेस्ट सीरीज़ में नहीं चुना गया था और सामने आया था कि कोच द्रविड़ ने उनसे बात करते हुए कहा था कि वह अब उनकी योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं। साहा इस समय आईपीएल में बेहतरीन लय में हैं, जहां उन्होंने 123.24 के स्ट्राइक रेट से 281 रन बनाए हैं, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं। साहा के अलावा टीम में युवा विकेटकीपर अभिषेक पोरेल हैं, जिन्होंने साहा की अनुपस्थिति में प्रभावित किया था। टीम में श्रीवत्स गोस्वामी का नाम नहीं है, जिन्हें पहले भी टीम में नहीं चुना गया था। गोस्वामी मौजूदा समय में इंग्लैंड में क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं।

दल में शमी के छोटे भाई मोहम्मद कैफ़ और बाएं हाथ के स्पिनर अंकित मिश्रा को भी चुना गया है, जिन्होंने अंडर-25 में अच्छा प्रदर्शन किया था। टीम में उनके अलावा शाहबाज़ अहमद और प्रदिप्ता प्रमाणिक भी बाएं हाथ के स्पिनर होंगे। अनुभवी मध्यम तेज़ गेंदबाज़ निलकंठ दास और ओपनर सुदीप घरामी को भी टीम में चुना गया है, वहीं बंगाल के जूनियर राज्य खेल मंत्री मनोज तिवारी भी दल का हिस्सा हैं।

बंगाल दल

अभिमन्यु ईश्वरन (कप्तान), मनोज तिवारी, ?ऋद्धिमान साहा (विकेटकीपर), मोहम्मद शमी, अनुस्तुप मजुमदार, सुदीप चटर्जी, शाहबाज़ अहमद, अभिषेक रमन, ऋतिक चटर्जी, सायन मंडल, मुकेश कुमार, आकाश दीप, इशान पोरेल, कौशिक घोष, ऋतविक रॉय चौधरी, प्रदीप्त प्रमाणिक, करण लाल, निलकंठ दास, सुदीप घरामी, अभिषेक पोरेल, मोहम्मद कैफ़, अंकित मिश्रा।

गांगुली को रोहित और विराट पर भरोसा : बीसीसीआई अध्यक्ष बोले-

कोहली और रोहित जल्द फॉर्म में आ जाएंगे उमरान चुने जाते हैं तो आश्चर्य नहीं होगा

मुंबई

आईपीएल के 15 वें सीजन में भारतीय टीम के टॉप स्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली का खराब फॉर्म जारी है। इसी साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में टी-20 वर्ल्ड कप होना है। ऐसे में इन दोनों बल्लेबाजों का फॉर्म मैनेजमेंट की चिंता बढ़ा रहा है। इस बीच इन दोनों बल्लेबाजों को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली का साथ मिला है। गांगुली ने एक इंटरव्यू में कहा, 'मैं विराट कोहली या रोहित शर्मा की फॉर्म को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूं। दोनों बड़े खिलाड़ी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कोहली जल्द ही फॉर्म में आ जाएंगे और टी-20 वर्ल्ड कप के लिए उनका टीम में चुना जाना भी तय है।'

उमरान के टीम इंडिया में चुने जाने के दिए संकेत

वहीं, गांगुली ने मौजूदा सीजन में सबसे तेज गेंद डालने वाले हैदराबाद के तेज गेंदबाज उमरान मलिक को टीम इंडिया में चुने जाने को लेकर भी संकेत दिए हैं। उमरान 12 मैच में 18 विकेट ले चुके हैं। गांगुली ने कहा, 'दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए अगर उमरान टीम में चुने जाते हैं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।'

रोहित का भी आईपीएल सबसे कमजोर प्रदर्शन: आईपीएल का 15वां सीजन टीम इंडिया के ओपनर और कप्तान रोहित शर्मा के लिए भी बहुत खराब रहा है। उन्होंने अपने आईपीएल करियर के सबसे कम औसत से रन बनाए हैं। अब तक खेले 12 मैचों में वे 18.17 की औसत और 125.29 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 218 रन ही बना सके हैं। इससे पहले उन्होंने आईपीएल में 2017 और 2018 में लगभग 24 की औसत से रन बनाए थे। उन्होंने 2017 में 17 मैचों में 23.78 की औसत से 333 रन और 2018 में 14 मैचों में 23.83 की औसत से 286 रन बनाए थे।

विराट ने एक मैच में बनाई हाफ सेंचुरी

कोहली इस सीजन में खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। उन्होंने 13 मैचों में 19.67 की औसत और 113.46 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 236 रन बनाए हैं। तीन बार वह डक पर भी आउट हुए हैं।

कोहली ने मौजूदा सीजन में एक ही हाफ सेंचुरी बनाई है।

आईपीएल करियर का यह दूसरा मौका है जब उन्होंने 20 के कम औसत से रन बनाए हैं। इससे पहले उन्होंने 2008 में अपने डेब्यू आईपीएल में 15 की औसत से रन बनाए थे। पिछले मैच में कोहली पंजाब के खिलाफ 20 रन बनाकर आउट हो गए। इस मैच में पंजाब किंग्स ने 210 रनों का विशाल स्कोर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के समक्ष रखा था।

कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद थी। उन्हें पारी के चौथे ओवर में कागिसो राबाडा ने आउट किया था। बेंगलुरु को 54 रन से हार का सामना करना पड़ा।

आईपीएल में किंग्स का अब सिर्फ एक मैच

रैंकिंग में 7वें नंबर पर टीम; पंजाब की हार के लिए बल्लेबाज जिम्मेदार

पंजाब

पंजाब किंग्स इलेवन को आईपीएल के 15वें सीजन में 13वें मैच में 7वीं हार मिली है। दिल्ली कैपिटल्स के 159 रनों का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम 142 रनों पर ही सिमट गई। दिल्ली ने 17 रनों से पंजाब को मात दी है। इस मैच को जीतने के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स ने अंतिम 4 में जगह बना ली है। वहीं पंजाब की टीम 7वें नंबर पर ही बनी हुई है। अब पंजाब का अंतिम शेड्यूल्ड मैच 22 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के साथ वानखेड़े के मैदान में होगा। नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला से कोचिंग में डिप्लोमा होल्डर क्रिकेट कोच संजीव पठानिया ने कहा कि गेंदबाजी में पंजाब ने अच्छा किया, मगर बल्लेबाजी एक बार फिर से फेल रही। लियाम लिविंगस्टोन ने 27 रन देकर 3 विकेट चटकाए। इसी तरह अर्शदीप सिंह ने भी कमाल दिखाया और 37 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। कगिसो रबाडा 1 ही विकेट ले पाए। गेंदबाजों ने कुल मिलाकर बढ़िया खेल दिखाया। टीम ने सिर्फ 9 एक्स्ट्रा रन दिल्ली को दिए।

छोटा लक्ष्य भी नहीं भेद पाए बल्लेबाज:- कोच पठानिया के मुताबिक, पंजाब के गेंदबाजों ने दिल्ली के स्कोर पर लगाम लगा दी थी और दिल्ली काफी छोटा लक्ष्य दे पाई थी। इसके बावजूद टीम के बल्लेबाज इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए। बल्लेबाजी में जितेश शर्मा ने 34 गेंदों पर 44 रन, जॉनी बेयरस्ट्रा ने 28 और गेंदबाज राहुल चाहर ने नाबाद 25 रन बनाकर अच्छा प्रयास किया, मगर बाकी बल्लेबाज फ्लॉप रहे। टीम के विस्फोटक बल्लेबाज शिखर धवन, भानुका राजपक्षा, कप्तान मयंक अग्रवाल और ऑल राउंडर लियाम लिविंगस्टोन नहीं चले।

पंजाब के हार के दोषी मयंक अग्रवाल

ओपनिंग के बाद मिडिल ऑर्डर में भी फेल, दूसरी बॉल पर बगैर खाता खोले बोल्ड हुए

पंजाब

पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए आईपीएल 15 के 64वें मुकाबले में पंजाब की हार के लिए कप्तान मयंक अग्रवाल को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पंजाब की टीम दिल्ली के खिलाफ 160 रनों का टारगेट हासिल नहीं कर सकी और 17 रनों से मुकाबला गंवा बैठी। पंजाब के कप्तान मयंक का प्रदर्शन अब तक पूरे सीजन निराशाजनक रहा था। ऐसे में उम्मीद थी कि टीम को प्लेऑफ की दौड़ में

मजबूती से बनाए रखने के लिए दिल्ली के खिलाफ वह दमदार प्रदर्शन करेंगे। मयंक ने फिर एक बार उम्मीदें तोड़ते हुए बगैर खाता खोले अपना विकेट गंवा दिया आमतौर पर मयंक अग्रवाल स्पिन को बेहतर खेलते हैं। इंसाइड आउट शॉट के जरिए काफी रन भी बटोरते हैं। इस सीजन लगातार रन के लिए तरस रहे मयंक दिल्ली के खिलाफ स्पिनर अक्षर पटेल की गेंद नहीं समझ सके और बोल्ड हो गए। अक्षर की गेंद अंदर की तरफ आ रही थी। मयंक ने उस बॉल को ऑफ साइड की तरफ खेलना चाहा, जबकि ऐसा करने के लिए अक्षर ने बिल्कुल रूम नहीं दिया था।

SUPER HERO

यदि आप

किसी भी व्यक्ति को जानते हैं
जिसने, सामाजिक सरोकार में
असाधारण प्रदर्शन किया हो,
वह व्यक्ति आप स्वयं भी हो सकते हैं,
दोनों स्थिति में हमें पूर्ण विवरण, भेजें।

हम देश के असली नायक
SUPER HERO MP 2021
SUPER HERO IND 2021
खोज रहें हैं, उन्हें समाज, राष्ट्र के सामने लाना और
सम्मान दिलवाना, आपका-हमारा सयुंक्त प्रयास रहेगा।

Contact: Editorial Desk (Lifestyle), ITDC News, 9826 220022
Email: responseitdc@gmail.com

PRESS ITDC
ITDC NEWS
www.itdcindia.com

इंग्लैंड के सफ़ेद गेंद क्रिकेट कोच बनने के प्रबल दावेदार हैं मैथ्यू मॉट

नई दिल्ली

ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के कोच मैथ्यू मॉट इंग्लैंड के सीमित ओवर कोच बनने के लिए प्रबल दावेदार बनकर उभर चुके हैं और ऐसा हो सकता है उनकी नियुक्ति इसी हफ़्ते में की जाए। ईएसपीएनक्रिकइंफ़ो को पता चला है कि साक्षात्कार के दौरान उनकी उम्मीदवारी पूर्व इंग्लैंड ऑलराउंडर पॉल कॉलिंगवुड से बेहतर मानी गई। कॉलिंगवुड हालिया समय में वेस्टइंडीज़ में अंतरिम कोच का काम कर चुके थे।

रॉब की के पुरुष क्रिकेट निदेशक नियुक्त होने के बाद इंग्लैंड ने टेस्ट और सीमित ओवर में कोचिंग भूमिकाओं को विभाजित करने का फ़ैसला किया था। पिछले हफ़्ते कोलकाता नाइट राइडर्स कोच और पूर्व न्यूज़ीलैंड कप्तान ब्रेंडन मक्कलम को टेस्ट टीम का कोच नियुक्त किया गया था। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) सलाहकार ऐंड्र्यू स्ट्रॉस और सीईओ टॉम हैरिसन

उनके साक्षात्कार करने वाले पैनल के सदस्य थे। सफ़ेद गेंद कोच के चयन प्रक्रिया में समझा जा रहा है कि कप्तान ओएन मॉर्गन की सलाह भी ली गई है। संयोग से मक्कलम ने लगभग 10 साल पहले मॉट की सिफ़ारिश न्यूज़ीलैंड के पुरुष टीम के मुख्य कोच पद के लिए की थी। उस वक़्त यह पद आख़िरकार माइक हेसन के पास गई थी।

48 वर्षीय मॉट 2015 से ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के साथ हैं। इस दौरान उन्होंने कप्तान मेग लानिंग के साथ इस टीम को इतना मज़बूत बनाया है कि उन्हें इंविंसीबल्स यानी अजेय के नाम से पुकारा जाने लगा है। 2017 में भारत के हाथ वनडे विश्व कप में हार मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अगले 42 मैचों में केवल दो हारे हैं और जीतने के सिलसिले में उन्होंने इस साल विश्व कप में भी सारे मैच जीते। खुद क्वींसलैंड और विक्टोरिया के शीर्ष क्रम बल्लेबाज़ रह चुके मॉट ने पुरुष क्रिकेट में न्यू साउथ वेल्ज़ और ग्लमॉर्गन के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ए के मुख्य कोच की भूमिका भी निभाई है। 2009 में वह कोलकाता नाइट राइडर्स के सहायक कोच भी थे। महिला विश्व कप के दौरान उनका नाम जस्टिन लैंगर की जगह पुरुष टीम में मुख्य कोच के पद के साथ भी जोड़ा गया था लेकिन उन्होंने तब कहा थी कि वह महिला टीम के साथ ही जुड़े रहना चाहेंगे।

न्यूज ब्रीफ

सीसीआई के दायरे में डिजिटल सौदे

नई दिल्ली। डिजिटल कारोबार में विलय और अधिग्रहण (एमऐंडए) के बड़े सौदों के लिए जल्द ही भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) से मंजूरी लेने की जरूरत पड़ सकती है। आयोग कुछ नए नियमों पर काम कर रहा है, जिनमें एक निश्चित मूल्य से अधिक के सौदों को उससे हरी झंडी लेनी होगी। कंपनियों को अब भी सीसीआई से मंजूरी की जरूरत पड़ती है मगर इसके लिए प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित परिसंपत्ति आकार और कारोबार ही पैमाने होते हैं। आयोग अब सौदे के आकार अथवा सौदे के मूल्य को भी पैमाना बनाना चाहता है ताकि डिजिटल उद्योग में होने वाले एमऐंडए के सौदों को भी इसके दायरे में लाया जा सके। पिछले कुछ समय में कई अहम सौदे मौजूदा नियमों के कारण सीसीआई से मंजूरी के बगैर ही कर लिए गए हैं। इनमें फेसबुक और व्हाट्सऐप का विलय भी शामिल है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया, डिजिटल फर्मों के गठजोड़ को विलय की समीक्षा के दायरे में लाने पर चर्चा चल रही है। नियामक इस सिलसिले में दुनिया भर में जारी तरीकों और नियमों की समीक्षा कर रहा है। जल्द ही वह इसके लिए पैमानों की शर्तें तथा सीमा तय कर सकता है।% उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रतिस्पर्द्धा कानून में संशोधन किया जा सकता है। इस संशोधन को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जा सकता है। इससे डिजिटल बाजार में होने वाले अधिग्रहणों पर सीसीआई का नियंत्रण बढ़ेगा। बड़ी तकनीकी और इंटरनेट कंपनियां हमेशा अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए मौके तलाशती रहती हैं। वे यूजर्स के बीच लोकप्रियता की संभावनाओं से भरी तकनीक वाली ऐसी स्टार्ट-अप खरीदती आई हैं, जिनकी कमाई कम होती है। एक अधिकारी ने बताया कि इस कारण ये सीसीआई के दायरे से बच निकलती हैं क्योंकि वर्तमान नियम ऐसे एमऐंडए सौदों की समीक्षा ही नहीं करने देते। सूत्रों का कहना है कि सौदे की कीमत की सीमा विकसित देशों में चल रही सीमा के आसपास ही हो सकती है। मसलन जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने 2017 में सौदे की कीमत की वैकल्पिक सीमाएं अपना ली थीं, जिनमें बड़ी कंपनियों को उन देशों में अहम गतिविधियों वाली कंपनियों के अधिग्रहण की सूचना देनी होती है चाहे छोटी कंपनियां कुछ भी नहीं कमा रही हों। जर्मनी में नए नियमों के तहत 40 करोड़ यूरो से अधिक वैश्विक मूल्य वाले सौदों और ऑस्ट्रिया में 20 करोड़ यूरो से अधिक वैश्विक मूल्य के सौदों की समीक्षा की जाती है। पचास से अधिक देशों में अब आवश्यक सीमा से कम के सौदों की प्रतिस्पर्द्धा संबंधी समीक्षा करने का विवेकाधीन अधिकार है। यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संघ के सदस्य देश और ब्रिटेन आदि अक्सर इस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। जेएसए में पार्टनर और प्रतिस्पर्द्धा कानून के हेड ऑफ प्रैक्टिस वैभव चौकसे कहते हैं, %नियामक के लिए यह बड़ी समस्या है क्योंकि डिजिटल क्षेत्र में जिन कंपनियों के लिए बड़े सौदे किए जाते हैं, उनके पास शायद अधिक संपत्ति नहीं हो या उनका कारोबार बड़ा ही नहीं हो।

कार खरीदने का बदलता ट्रेंड : महंगी कारों की बिक्री 38 फीसदी की दर से बढ़ी, जबकि सस्ती कारें सिर्फ 7 फीसदी रही

नई दिल्ली

कोरोना ने जीवन के तमाम पहलुओं को बदल दिया है। इस दौरान ऑटो इंडस्ट्री में भी बदलाव हुए है। दो साल में महंगी कारों की बिक्री सस्ती कारों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ी है। घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिसर्च के मुताबिक, एंट्री लेवल कारों के मुकाबले 10 लाख रु. से ज्यादा कीमत वाली कारें तेजी से बिकने की मुख्य वजह दोनों सेगमेंट के ग्राहकों की आमदनी में अंतर है। 2021-22 में प्रीमियम सेगमेंट यानी 10 लाख रुपए से अधिक कीमत वाली कारें सस्ती कारों की तुलना में 5 गुना तेजी से बिकीं। रिपोर्ट बताती है कि प्रीमियम सेगमेंट की कारों की बिक्री सालाना 38 फीसदी की दर से बढ़ी है।

जबकि, सस्ती कारों की बिक्री सालाना 7 फीसदी की दर से बढ़ रही है। इससे 2021-22 में प्रीमियम कारों का मार्केट शेयर 25 फीसदी से बढ़कर 30 फीसदी हो गया।

छोटी कारों की लॉन्चिंग भी कम हुई:- 2018-19 में मारुति की अल्टो, स्विफ्ट, बलेनो, विटारा ब्रेजा, सेलेरियो और डिजायर और हुंडई की आई10 और आई20 की कम कीमत वाली कारों की बिक्री में हिस्सेदारी 56 फीसदी थी। बीते तीन साल इसमें तेजी से गिरावट आई। वर्ष 2015-16 में बाजार में कम कीमत वाले 54 मॉडल थे, जबकि 2021-22 में इसकी संख्या 39 रह गई। 2019-20 के बाद कम कीमत वाली कारों के सेगमेंट में नई कारें भी कम आई हैं। 2021-22 में इनकी हिस्सेदारी महज 15 फीसदी रही। महंगी कारों की बात करें तो 2018-19 में हुंडई की क्रेटा, मारुति की अर्टिगा, सियाज, महिंद्रा की बोलेरो, स्कॉर्पियो, होंडा सिटी, फोर्ड इकोस्पोर्ट और टोयोटा इनोवा की हिस्सेदारी 68 फीसदी थी। 2019 के बाद इसमें गिरावट आई, लेकिन इसकी भरपाई इस सेगमेंट में हुई नई लॉन्चिंग ने कर दी।

दोपहिया: 70 हजार से महंगी गाड़ियां ज्यादा

दोपहिया सेगमेंट की बात करें तो 5-6 साल में 70 हजार रुपए से अधिक कीमत वाली गाड़ियों की बिक्री कम कीमत वाले स्कूटरों से अधिक रही। दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियां अधिक कीमत वाले सेगमेंट पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। 2014-15 में लोअर-प्राइस सेगमेंट में 29 मॉडल थे। अब इनकी संख्या 12 है। हायर-प्राइस सेगमेंट में दोपहिया मॉडलों की संख्या 2014-15 में 71 थी, जो अब बढ़कर 93 पर पहुंच गई है।

एलआईसी की कमजोर लिस्टिंग : मार्केट कैप के लिहाज से 5वीं बड़ी कंपनी बनी

949 रुपए के मुकाबले 867 रुपए पर लिस्ट हुआ शेयर

मुंबई

एलआईसी के शेयर्स की लिस्टिंग डिस्काउंट के साथ हुई है। एनएसई पर एलआईसी का शेयर 77 रुपए, यानी 8.11 फीसदी नीचे 872 रुपए पर लिस्ट हुआ है। वहीं, बीएसई पर ये 867 पर पर लिस्ट हुआ है। सरकार ने एलआईसी में अपनी 3.5 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर करीब 21,000 करोड़ रुपए हासिल किए हैं। इश्यू 2.95 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इश्यू का अपर प्राइस बैंड 949 रुपए था। यानी जिन निवेशकों को शेयर में डिस्काउंट नहीं मिला उन्हें बीएसई प्राइस के हिसाब से प्रति शेयर 82 रुपए का नुकसान हुआ है। लिस्टिंग प्राइस के हिसाब से एलआईसी का मार्केट कैप 5.48 लाख करोड़ रुपए रहा। ये देश की 5वीं वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। एलआईसी से आगे केवल इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस और रिलायंस इंडस्ट्रीज है।

निवेशकों को लिस्टिंग पर कितना नुकसान:- पॉलिसीधारकों को: एलआईसी ने 15 शेयर का लॉट साइज रखा था। अगर आपने पॉलिसी धारक कोटे से आईपीओ में अप्लाय किया था तो आपको 60 रुपए का डिस्काउंट, यानी एक शेयर (949-60) 889 रुपए में मिला। इस हिसाब से 889 म 15 = 13,335 रुपए में 1 लॉट यानी 15 शेयर मिले। वहीं बीएसई पर शेयर 867 रुपए पर लिस्ट हुआ। यानी, पॉलिसीधारकों को लिस्टिंग पर प्रति शेयर 22 रुपए का नुकसान हुआ और 1 लॉट पर ये नुकसान 330 रुपए का रहा।

रिटेल और कर्मचारियों को:- अगर आपने रिटेल और कर्मचारी के कोटे से आईपीओ में अप्लाय किया था तो आपको 45 रुपए का डिस्काउंट, यानी एक शेयर (949-45) 904 रुपए में मिला। इस हिसाब से 904 म15 = 13,560 रुपए में 1 लॉट, यानी 15 शेयर मिले। बीएसई पर शेयर 867 रुपए पर लिस्ट हुआ। यानी, रिटेल और कर्मचारियों को लिस्टिंग पर प्रति शेयर 37 रुपए का नुकसान हुआ। 1 लॉट पर ये नुकसान 555 रुपए का रहा।

मैक्वायरी ने दिया 1000 रुपए का टारगेट प्राइस

विदेश ब्रोकरेज फर्म मैक?वायरी ने एलआईसी के 1000 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ इसे न्यूट्रल रेटिंग दी है। 5 करोड़ रुपए की सरकारी रकम से शुरू हुई कंपनी, अब तक सरकार को दे चुकी है 23 लाख करोड़

इश्यू 2.95 गुना सब्सक्राइब हुआ था

एलआईसी के आईपीओ को निवेशकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। हालांकि, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के बावजूद ये विदेशी और संस्थागत निवेशकों को लुभाने में विफल रहा। रिटेल और अन्य निवेशकों के लिए 4 मई को खुले इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन का 9 मई को आखिरी दिन था। इश्यू 2.95 गुना सब्सक्राइब हुआ था।

पॉलिसीधारकों का पोर्शन 6.10 गुना भरा:- पॉलिसीधारकों के लिए रिजर्व रखा गया पोर्शन 6.10 गुना, स्टाफ 4.39 गुना और रिटेल निवेशकों का हिस्सा 1.99 गुना सब्सक्राइब हुआ है। त्त्ढ्ढक्क के आवंटित कोटे के लिए 2.83 गुना बोलियां आई हैं, जबकि ह्ढ्ढ का हिस्सा 2.91 गुना सब्सक्राइब हुआ है। 17 मई को शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। ज्यादातर मार्केट एनालिस्ट ने आईपीओ में पैसा लगाने की सलाह दी थी।

ट्राई का सिल्वर जुबली समारोह

प्रधानमंत्री मोदी ने 5जी टेस्टबेड किया लॉन्च

इससे भारतीय उद्योग और स्टार्टअप को मिलेगी मदद

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 5जी टेस्टबेड को लॉन्च किया है। ये देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री और स्टार्टअप को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा ये उनके प्रोडक्ट्स, प्रोटोटाइप और सॉल्यूशन को पांचवें जेनरेशन में वैलिडेट करेगा। ट्राई के सिल्वर जुबली समारोह के मौके पर पीएम मोदी ने कहा, मुझे देश को अपना, खुद से निर्मित 5जी 5जी टेस्ट बेड राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिला है। ये टेलिकॉम सेक्टर में क्रिटिकल और आधुनिक टेक्नॉलॉजी की आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक अहम कदम है। मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को, हमारे IITs को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

8 इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर किया है डेवलप

5जी टेस्टबेड को टोटल 8 इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर डेवलप किया है। इसे आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में डेवलप किया गया है। इस प्रोजेक्ट में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी बाम्बे, आईआईटी कानपुर, IISc बैंगलोर, सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च और सेंटर आफ एक्सिलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी शामिल हैं।

इस प्रोजेक्ट में 220 करोड़ से ज्यादा की लागत आई

इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में 220 करोड़ से ज्यादा की लागत आई है। ये टेस्टबेड इंडियन इंडस्ट्री और स्टार्टअप के लिए सपोर्टिव इकोसिस्टम को उपलब्ध कराएगा।

क्या है 5जी टेस्टबेड?

5जी टेस्टबेड भारतीय उद्योग और स्टार्टअप के लिए एक सहायक इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा। ये उन्हें 5जी और अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी में अपने उत्पादों, प्रोटोटाइप, समाधान और एल्गोरिदम को मान्य करने में सहायक होगा।

पवन हंस की बिक्री टाल सकती है केंद्र सरकार

नई दिल्ली

सरकारी स्वामित्व वाली हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता कंपनी पवन हंस लिमिटेड की बोली जीतने वाले कंसोर्टियम के एक सदस्य के खिलाफ अदालती आदेश आने के कारण केंद्र इसकी बिक्री अनिश्चित समय के लिए टाल सकता है। यह दूसरा मामला है, जिसमें विजेता बोलीदाता के खिलाफ आरोपों की वजह से प्रक्रिया पूरी होने के बाद विनिवेश की मुहिम को टाला जा रहा है। सरकार ने पहले सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) का निजीकरण रोक दिया था। उस मामले में आरोप थे कि बोली जीतने वाली कंपनी नंदलाल फाइनैंस और छांट दी गई दूसरी कंपनी जेपीएम

इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक-दूसरे से संबंधित हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अल्मास ग्लोबल अपॉर्च्युनिटी फंड अपने पिछले रिकॉर्ड की वजह से सवालों के घेरे में है। यह केमन द्वीपसमूह का फंड है, जिसे दुबई की अल्मास कैपिटल संभालती है। इसे राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने दोषी ठहराया है क्योंकि बोली में सफल घोषित किए जाने के बाद भी आवश्यक धनराशि का भुगतान नहीं किया और कोलकाता की बिजली पारेषण कंपनी ईएमसी लिमिटेड की दिवालिया प्रक्रिया को मुश्किल में फंसा दिया। एनसीएलटी के कोलकाता पीठ ने 20 अप्रैल को आदेश दिया कि दिवालिया संहिता की धारा 74(3) के तहत अल्मास ग्लोबल अपॉर्च्युनिटी फंड के प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस धारा के तहत बोली जीतने वाली कंपनी के अधिकारियों को कम से कम एक साल और अधिकतम पांच साल के लिए कैद किया जा सकता है। उन पर अधिकतम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

हवाई यात्रियों की तादाद में दिखी बढ़ोतरी

मुंबई

ताजा हफ्ते के दौरान विभिन्न गतिविधियों में तेजी आई। एक हफ्ते पहले के मुकाबले ताजा हफ्ते में रोजाना औसतन करीब 10,000 से अधिक लोगों ने विमान यात्रा की। हवाई यात्रियों की संख्या में बढोतरी के रुझान दिख रहे हैं। रविवार 15 मई को ही 400,000 से अधिक हवाई यात्री थे। हफ्ते के दौरान यात्रियों की कुल तादाद करीब 26 लाख थी। सर्च इंजन गूगल के आंकड़ों के मुताबिक ट्रांजिट क्षेत्रों मसलन बस स्टॉप, रेलवे स्टेशनों में अधिक गतिविधि देखी जा रही है। यह अनाम लोकेशन डेटा का इस्तेमाल कर विभिन्न जगहों के मोबिलिटी डेटा का संग्रह करता है। आखिरी दो दिनों के उपलब्ध डेटा दर्शाते हैं कि ट्रांजिट क्षेत्रों में अधिक गतिविधि दिखी है। बिजली उत्पादन उच्चतम स्तर पर रहा लेकिन गर्म हवाओं और देश के उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम हिस्से में रिकॉर्ड स्तर के तापमान के बावजूद इसमें बढ़ोतरी नहीं हो पाई। देश में बिजली संयंत्रों ने 15 मई को खत्म हुए सप्ताह के दौरान रोजाना औसतन 460

लाख करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन किया जो चालू वित्त वर्ष 2019 में समान हफ्ते के दौरान 400 यूनिट बिजली उत्पादन के मुकाबले 14.8 फीसदी अधिक रहा। बिजली उत्पादन हफ्ते दर हफ्ते के आधार पर 1.25 फीसदी अधिक रहा। ताजा हफ्ते के दौरान भारतीयों ने कुल 384,594 वाहनों का पंजीकरण कराया। 2019 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले समान अवधि के दौरान यह 5.2 फीसदी कम था। लेकिन यह अंतर पिछले हफ्ते के मुकाबले कम था जब पंजीकरण में 18.5 फीसदी की कमी आई। वैश्विक लोकेशन तकनीक कंपनी टॉम टॉम इंटरनैशनल के आंकड़े के मुताबिक सोमवार सुबह 9 बजे मुंबई और नई दिल्ली में यातायात भीड़ में कमी आई। नई दिल्ली में यह 2019 के मुकाबले 56 फीसदी कम था जबकि पिछले हफ्ते के मुकाबले यह 39 फीसदी कम था। इसकी वजह बुद्ध पूर्णिमा की सरकारी छुट्टी भी हो सकती है। मुंबई में यातायात में 63 फीसदी की कमी आई जबकि पहले इसमें 48 फीसदी की कमी दिखी थी। रेलवे के आंकड़े भी स्थिर रहे। भारतीय रेलवे के जरिये होने वाली माल ढुलाई की तादाद में सालाना वृद्धि एक हफ्ते पहले के 14.87 फीसदी की तुलना में 14.81 फीसदी रही। भारतीय रेलवे की सामान ढुलाई से होने वाली कमाई में वृद्धि पिछले हफ्ते के 23.06 फीसदी की तुलना में 20.57 फीसदी रही। बिज़नेस स्टैंडर्ड इन संकेतकों का जायजा इसलिए लेता है ताकि अर्थव्यवस्था की साप्ताहिक तस्वीर का अंदाजा मिल सके। आधिकारिक स्तर पर वृहद अर्थव्यवस्था के आंकड़े थोड़े अंतराल के बाद आते हैं। वैश्विक स्तर पर भी विश्लेषक समान संकेतकों पर नजर रख रहे हैं ताकि जमीनी स्तर पर स्थिति का अंदाजा लग सके क्योंकि विभिन्न देशों की सरकारों ने भी कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। यातायात से जुड़े आंकड़े 16 मई के हैं जबकि गूगल के आंकड़े 11 मई के हैं। बाकी सभी सूचनाएं रविवार 15 मई की हैं।

इंटीग्रेटेड ट्रेड डेव्हेलप सेंटर न्यूज के लिए मालिक, मुद्रक एवं प्रकाशक राधिका वीरेंद्र, स्वामी- इंटीग्रेटेड ट्रेड डेव्हलपमेंट सेंटर इंडिया ईप्रेस द्वारा साई प्रिंटर्स, 91 जहांगीराबाद भोपाल से मुद्रित करवाकर, श्री परिसर, 23 पश्चिम निशातपुरा, डीआईजी बंगला, भोपाल से प्रकाशित। संपादक- राधिका वीरेंद्र।
आरएनआई क्र. MPHIN/2018/77221, फोन- 0755-42223334, पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल होगा।)